मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 31 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 30 जुलाई – 5 अगस्त 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

मुनाफे के लिए भोजन–भारत का लक्ष्य.....3

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम...5

मणिपुर में हिंसा के खिलाफ भाकपा के विरोध की झलकियां 8–9

मणिपुर हिंसा पीड़ितों के साथ एकजुटता का आह्वान

भाकपा ने 25 जुलाई को देशभर में मनाया मणिपुर दिवस

भाकपा महासचिव डी. राजा चेन्नई में मणिपुर दिवस का उद्घाटन करते हुए

हमारे विशेष संवाददाता द्वारा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की देश भर की शाखाओं ने और जन संगठनों ने पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के आह्वान पर 25 जुलाई को मणिपुर की जनता के साथ एकजुटता दिवस के तौर पर मनाया। हर कहीं लोगों ने इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। चैन्नई में मणिपुर की जनता के साथ एकजुटता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि 3 मई से मणिपुर में हिंसा जारी है और शांति बहाल नहीं हो पाई है। मणिपुर और केंद्र की भाजपा सरकारों ने मणिपुर की जनता को निराश किया है और उनके शांतिपूर्ण एवं खुशहाल जीवन के अधिकार को बनाए रखने में नाकाम रही हैं। राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लंबे अरसे से की जा रही लापरवाही के कारण और जमीन के जटिल मुद्दे, विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों की पहचान, वनों की जमीन के दुरूपयोग, बेरोजगारी और अन्य ज्वलंत मुद्दों का समाधान न निकाले जाने के कारण वर्तमान जातीय टकराव हुआ है।

केरल

केरल में लगातार बारिश के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर 25 जुलाई को मणिपुर की जनता के साथ एकजुटता दिवस मनाने के कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तिरूवनन्तपुरम में शहीद स्तंभ के पास एकजुटता दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के राज्य सचिव पी.पी. सुनीर ने किया। कन्याकुलंगरा में पूर्व राज्य सचिव पन्नियन रवीन्द्रन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। किलिमन्नूर में पार्टी के राज्यकार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट एन. राजन और कमलेश्वरम में पार्टी के जिला सचिव एम. राधाकृष्णन ने एकजुटता दिवस मीटिंग को संबोधित किया।

कोल्लम में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट के. प्रकाश बाबू, कसरगोड में पार्टी के राज्य सहसचिव ई. चन्द्रशेखरन, विधायक, कोझिकोड और कन्नूर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एनी राजा ने एकजुटता दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

पोन्नानी में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य के.पी. राजेन्द्रन, पलक्कड़ में पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजाजी मैथ्यू थॉमस, एर्नाकुलम में राज्य कार्यकारिणी सदस्य के.के. अशरफ, पत्तनमतित्ता में पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य एम. रत्नाकरन, कोट्टायम में सी.के. शशिधरन, तोडुपुझा में इदुक्की पार्टी जिला सचिव के. सलीम कुमार, मुलामत्तम में पार्टी के राज्य परिषद सदस्य के. शिवारमन ने एकजुटता दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अलप्पुझा में 100 स्थानों पर रात्रि मार्च निकाले गए। तकाझी में अलप्पुझा जिले के पार्टी जिला सचिव टी.जे. अंजलोसे और तिरुनल्लूर में ए. आई.वाई.एफ राज्य सचिव टी.टी. जिस्मोन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। त्रिशूर में विभिन्न स्थानीय पार्टी कमेटियों ने एकजुटता दिवस कार्यक्रम किए। पार्टी के राज्य परिषद सदस्य शीला विजयकुमार, के.पी. संदीप और एटक के जिला अध्यक्ष के. सुदीश ने एकजुटता दिवस कार्यक्रमों को संबोधित किया।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आवाहन पर मणिपुर में हुई दरिंदगी के विरुद्ध एवं मणिपुर की जनता के प्रति भाईचारा व्यक्त करने के लिए प्रदेश भर में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए और राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन के नेताओं पर लगाए गए झूठे मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की गई।

पार्टी के राज्य कार्यालय से जारी एक बयान में पार्टी के राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप ने बताया की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आवाहन पर आज पूरे प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने धरने प्रदर्शन आयोजित करके महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में महिलाओं के विरुद्ध हुई दरिंदगी की घोर निंदा की और वहां की जनता के साथ अपना भाईचारा व्यक्त किया महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन के नेताओं पर भी झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए।

ज्ञापन में कहा गया कि मणिपुर, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में और म्यांमार सीमा से लगा हुआ एक सामरिक महत्व का अति संवेदनशील राज्य है जिसकी परिस्थितियां गंभीर हैं।

3 मई से लेकर अब तक 142 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 1000 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं और 70000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं।

स्थिति अत्यंत बेरहम और शोचनीय है। वहां के नागरिक अपने ही देश में लगभग 272 शरणार्थी शिविरों में शरण लिए हुए हैं। कुछ हजार लोगों ने निकट के राज्यों और दिल्ली में पनाह ली हुई है।

19 जुलाई को एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जिसमें एक भीड़ है। दो नग्न लड़की बंधक है। बताया गया कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है। लोफर अपराधी उनको सड़क पर घुमा रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है की दो लोफर एक नग्न लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे हैं। भारत देश में ऐसा हो रहा है। इससे बड़ी निंदनीय कोई चीज नहीं। पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं की ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं जब से हिंसा शुरू हुई है हो चुकी है।

इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि उक्त 2 महिलाओं में से एक ने बताया कि मणिपुर पुलिस ने ही उनको भीड़ के हवाले कर दिया। ऐसी स्थिति पैदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है।

इस वीभत्स घटना से सारा देश गुस्से में है। प्रदेश और देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि उन्होंने देश को किस अधो गति पर पहुंचा दिया।

यह हिंसा 3 मई को विभिन्न आदिवासी लोगों द्वारा आयोजित एकजुटता रैली से शुरू हुई। बीजेपी और आरएसएस ने और उनकी सरकारों ने आदिवासियों की सामाजिक स्थिति और आदिवासी अधिकारों के प्रश्न को इस तरह से उभारा गया कि उसके

शेष पेज 12 पर...

दहकता मणिपुर

संपादकीय

पूरे विडियो में, हम, जो अपनी इंसानियत का दावा करते हैं, दिखाई दे रहे थे। यह सारा कुछ प्रतिबिंबित कर रहा था हमारे अंदर बसे उस अपराधी को, जो किसी भी हद को पार कर रहा था। और यही सब कुछ नहीं था। कितनी देर लग सकती है अदम्य पीड़ा से जूझती उस माँ की आंसुओं में डूबी चीखों को सुनाई देने में? और पहुंच पाने में? राजसत्ता, यानी पुलिस ने, उस मां के ही शब्दों में, उन्हें ''भीड़ को सौंपा था।'' उसके सामने उसे पिता और भाई के विरोध करने पर उन्हें ख़त्म कर दिया गया। अंततः जब उसने आतताइयों से प्रार्थना की जीवनदान की और कहा कि उसकी हत्या का अर्थ है उसके चार साल के बच्चे की भी हत्या, तो उसे जीवनदान मिला, लेकिन सशर्त, ''मरो या हमें अपने को सौंप दो।'' यह नियति सिर्फ एक की नहीं, असंख्यों की कहानी थी, अनकही और अनसुनी। मणिपुर की घटनाओं से सिर्फ देश ही नहीं, पूरा विश्व स्तब्ध है।

हमारी गंगा–जमुनी संस्कृति, संविधान और जनवादी बुनियाद, कग़ार पर पहुंचे हुए है। हमारे भारत में कभी ऐसी बर्बरता देखी नहीं गई थी। बेलगाम हिंसा, यहां तक कि वहां की महिलाओं का पूरा घायल वजूद ही इस भयंकर स्थिति को सामने ला रहा था। इस सबके विरूद्ध सत्ता कोई क़दम नहीं उठा रही थी। एफआईआर के दायर होने के आज क़रीब तीन महीने में एक भी क़दम नहीं उठाया गया। अब, जब पूरा देश और विश्व इसकी तीक्ष्ण आलोचना कर रहा है, तो क़दम उठा रहे हैं। यह ख़ामोशी बरकरार चल रही थी बावजूद गृहयुद्ध के अंदेशे के। तीस लाख लोगों की इस बेहद खूबसूरत जमीन पर हिंसा का भयानक दौर चल रहा है। बहुसंख्यक मैइती और अल्पसंख्यक कूकी संप्रदायों में इस असंतोष की बुनियाद की शुरुआत हुई जब मई 3, 2023 को मणिपुर, हाईकोर्ट ने मैइती संप्रदाय, जो अपने को हिन्दू कहते हैं, इन्हें शिड्यूल ट्राइब (एस.टी.) का स्टेट्स दिया और कूकी को नहीं।

पहले से चले आ रहे भयंकर असंतोष का बांध खुल गया। उस दिन से अब तक 142 लोगों की हत्या हो चुकी है। हज़ारों घायल हैं, उनके घर और गांव जल रहे हैं। उनकी जीविका ख़त्म हो चुकी है। क़रीब सत्तर हज़ार लोगों की यह स्थिति चल रही है। 271 शरणार्थी शिविर चल रहे हैं, लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो चुके हैं। वे भटक रहे हैं, आश्रय के लिये, सुरक्षा के लिये, खाने के लिये, दवा के लिये। कई हज़ार लोग पड़ोसी राज्यों में शरण लेकर रह रहे हैं। बहुत सारे दिल्ली में भी हैं। कई महीने गुजर गए, शांति अभी भी दूर दिखाई देती है।

केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें विफल हो चुकी है अपने ही राज्य में जनता को शांति दिलाने में। इस जातीय हिंसा की शुरुआत होने का मूल कारण ही है जनता के पास किसी अधिकार का नहीं होना। सरकार की तरफ से उनकी लंबे समय से चली आती उपेक्षा और किसी भी समस्या को सुलझाने में सरकार की असफलता, उनकी जमीनी समस्या के हल करने में भारी निरपेक्षता और अनिच्छा, जंगल की जमीन का दुरुपयोग, उसे अदानी के हाथों कोयले की ख़दानों के लिये बेचना, आजीविका का पूरा अभाव, शिक्षा के अवसरों में भयानक असमानता, अफीम की खेती की अनुमति, जंगल और जमीन का इसके लिये दुरुपयोग, भूमिगत संगठनों को घाटी और पहाड़ी इलाकों से हटाना, उन पर कार्रवाई करना, म्यांमार से लगातार आती आबादी को रोकने में नाकामी आदि। अनसुलझी समस्याएं लोगों की ज़िन्दगी मुश्किल कर रही है और सरकार को उन्हें सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस सबके बाद भी सबसे कठिन समस्या है संघ द्वारा चलाया गया लोगों को टुकड़ों में बांटने का अभियान और इस सबके साथ आसाम के मुख्यमंत्री की इस हिंसा में भूमिका, इन सबकी निन्दा देश में हो रही है। भाजपा सरकार की मणिपुर की परिस्थिति सुलझाने में विफलता ही इस हिंसा की त्रासदी को जीवित रखने में सहायक है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिये। सभी आतंकवादी संगठनों को निशस्त्र करना चाहिये, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिये। जंगल के रिजर्व इलाकों में अफीम की खेती में रोक लगानी चाहिये। जलवायु के संतुलन को बचाने की कोशिश करनी चाहिये। लोगों को फिर से बसाने की कोशिश करनी चाहिये। उन्हें मुआवजा मिलना चाहिये।

निश्चित अवधि के अंदर उन्हें आजीविका मिलनी चाहिये। सारे मुख्य रास्ते खुल जाने चाहिये ताकि उन्हें बुनियादी जरूरत की चीजें मिल सके।

इन सबके लिये वस्तुस्थिति समझने की कोशिशें जब होती हैं, तो उन्हें रोकने के लिये एफ.आई.आर. लगा दिये जाते हैं। हमारी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की जनरल सेक्रेटरी एनी राजा, सी.पी.आई. की एक प्रमुख नेता और एनएफआईडब्ल्यू की सेक्रेटरी निशा सिद्धू और दीक्षा द्विवेदी, जो वकील हैं दिल्ली में, इन तीनों की फैक्ट फाईडिंग टीम मणिपुर पहुंची थी और वहां की हिंसा से जूझती जनता की स्थिति का उन्होंने अध्ययन किया, बातचीत की, और रिपोर्ट तैयार की, जो छपी और पढ़ी गयी। लेकिन इस टीम पर भी एफआईआर लगा दी गयी। सरकार को यह एफआईआर वापस लेनी चाहिये।

सी.पी.आई. इस सबमें मणिपुर की त्रासद ज़िन्दगी से जूझती जनता के साथ है और मणिपुर राज्य में एकता, शांति, और जनता की एकता कायम रखने की मांग करती है।

भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों का जातीय द्वन्द्व का एक इतिहास रहा है। यह 1947 से भी पहले से चला आ रहा है। मैइती और कूकी संप्रदायों में कई बार पहले भी अशांति हुई है। सरकार पर भी यह आरोप है कि उसने कूकी संप्रदाय के साथ अलगाव की नीति अपनायी है, उन्हें कई बार जबरन निकालने की धमकी भी दी गई, और ज़मीन से भी हटाने का निर्णय लिया गया। परिस्थितियां जब गर्म होने लगी तो तनाव भी भड़क उठा। राज्य सरकार में मैइती संप्रदाय के लोग अधिक हैं।

हिंसा तब भी भड़क उठी जब मणिपुर हाईकोर्ट ने मार्च में बहुसंख्यक मैइतियों को पहाड़ पर जमीन खरीदने की अनुमति दे दी। कूकी पहाड़ों में रहते हैं और मैइती घाटी में। कूकी कोर्ट के इस निर्णय से डर गए। उनके डर को भड़काया गया, जमीन, जीविका और अवसर छिन जाने का डर दिखाया गया। इससे विरोध की शुरुआत हुई। मुख्यतः कूकी छात्रों के ग्रुप से इसकी शुरुआत हुई। उनके बीच हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। मई का महीना आते–आते कूकी और मैइती समुदायों के बीच की दूरी बढ़ती गई और हिंसा की भयंकरता भी। राज्य जल्द ही जातीय स्तर पर भी स्पष्ट रूप से बंट गया। मैइती घाटी में और कूकी पहाड़ों में, अपनी जमीनों की लड़ाई लड़ते रहे। स्वयं ही अपने क्षेत्रों की सुरक्षा में लगे हुए है। एक– दूसरे के क्षेत्र में पैर रखना भी संभव नहीं है, प्राणों की क़ीमत पर ही यह हो सकता है। यद्यपि केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर सत्ता भाजपा के हाथों में ही है, उन्होंने यह घोषणा भी की है कि स्थिति शांत हो चली है, और छोटी–मोटी मुठभेड़ तो चलती ही रहती है। लेकिन वास्तव में दोनों पक्षों ने सावधान कर दिया है कि मणिपुर गृहयुद्ध की कगार पर है।

हम सब आज, देश में और विश्व में भी, मणिपुर की जनता के दर्द में शामिल हैं। हम अपने संविधान के साथ हैं और अपनी गंगा–जमुनी संस्कृति पर कोई आंच भी नहीं आने देंगे। इसलिये, सी.पी.आई ने जुलाई 25 का दिन, मणिपुर के नाम कर दिया है। कोने–कोने से, देशभर से इस दिवस के सामूहिक पालन के विवरण आ रहे है।

इंडिया से प्रधानमंत्री डर गए हैं

पटना, 26 जुलाई, 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से डर गये हैं। कड़ी चुनौती मिलने के कारण इंडिया को आतंकी संगठन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जोड़ रहे हैं। 2024 में केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई तय है। अपनी सत्ता जाते देख प्रधानमंत्री बौखलाहट में अनर्गल बयान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की परेशानी ओर बढ़ने वाली है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री तानाशाह की तरह बोलने लगे हैं। एनडीए के कार्यकाल में लोकतंत्र और संविधान पर हमले तेज हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि केंद्र सरकार उन राज्यों में कार्रवाई नहीं कर रही है, जहां भाजपा की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी नागालैंड में महिलाओं के लिए आरक्षण मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि इंडिया लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संकल्पित हैं। भाजपा सरकार संविधान और लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। प्रधानमंत्री देश को फासीवादी रास्ते पर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर जवाब देने से भाग रहे हैं। जब प्रधानमंत्री को करारा जबाब मिलने लगा है तो वे गठबंधन पर ही सवाल खड़ा करने लगे हैं।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार को देश की गरीब जनता की नहीं पूंजीपतियों की चिंता है। सरकार पूंजीपतियों के हित में ही सभी निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री ने जो सवाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर उठाया है, इसका जवाब देश की जनता अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाकर देगी।

भाकपा का आशा, आशा फैसिलिटेटर और स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर की हड़ताल को समर्थन

भाकपा की मांग; आंदोलनकारियों से वार्ता करे सरकार

पटना, 24 जुलाई, 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आशा, आशा फैसिलिटेटर, स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर, एटक की संयुक्त बैनर के तले 14 सूत्री मांगों को लेकर 17 जुलाई से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया है और राज्य सरकार से आंदोलनकारियों से वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराने की मांग की है।

भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि आशा और स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर की मांग जायज है। सरकार तत्काल आशा, आशा फैसिलिटेटर, स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर लोगों को 25000 रुपये वेतन एवं सरकारी कर्मचारी का दर्जा सहित उनके 14 सूत्री मांगों पर सहानूभूति पूर्वक विचार करे। सरकार दमनात्मक रूख अपनाने के बजाए उनसे वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में पहल करें। राज्य की 90 हजार से अधिक आशा–आशा फैसिलिटेटर कर्मी हड़ताल पर हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है। उन्हें न केवल जीने लायक मासिक मानदेय मिलता है और न हीं रिटायरमेंट का कोई लाभ मिलता है, केवल पारितोषिक कहकर एक हजार रूपया मानदेय दिया जाता है, जिसका अधिकांश हिस्सा यात्रा में ही खर्च हो जाता है। इतनी कम राशि में परिवार चलाना संभव नहीं है। कोरोना काल में उनकी भूमिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा बावजूद उन्हें न्यूनतम मासिक मानदेय नहीं मिलना उनके साथ अन्याय है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज स्कीम वर्करों की माली हालत खराब है।

उन्होनें बिहार सरकार से आंदोलनरत आशा और वैक्सीन कुरियर के नेताओं से वार्ता कर उनकी मांगों को मानने तथा इसके लिए केन्द्र सरकार पर दबाब बनाने की अपील की।

मुनाफे के लिए भोजन–भारत का लक्ष्य

डॉ. भालचन्द्र कांगो

1984 के बाद से–कृषि उद्योग में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने महसूस किया है कि दुनिया की बढ़ती आबादी को भोजन की आवश्यकता है और इसलिए यदि खाद्य उद्योग को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं तो लाभ की काफी संभावना है। इसलिए 1987 में उरुग्वे में गैट बैठक विफल हो गई क्योंकि विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी समर्थक सरकारों ने गैट में कृषि को शामिल करने पर जोर दिया और गैट व्यवस्था को छोड़ दिया गया और 1995 में इसकी जगह डब्ल्यूटीओ ने ले ली।

चूंकि अधिकांश विकासशील देश अपने किसानों और लोगों की रक्षा करना चाहते थे और खाद्य आपूर्ति में अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और 2010 तक उन्हें कुछ रियायतें दी गई। लेकिन धीरे–धीरे और निश्चित रूप से खाद्य उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एकीकरण अब एक वास्तविकता है और अधिकांश राष्ट्रीय सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मजबूत नियंत्रण के तहत बहुराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने के लिए खाद्य उद्योग को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनों को बदलने के लिए उस वास्तविकता का सामना करने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। पहले यह माना जाता था कि विकसित देश औद्योगिक रूप से उन्नत हैं और इसलिए कृषि व्यवसाय उनकी विशेषता नहीं है। हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार चर्चा से यह स्पष्ट है कि अमेरिका की मुख्य रुचि विशाल चीनी बाजार में सोया और अन्य कृषि उत्पादों को बेचने में है।

इसी प्रकार संकर या संशोधित बीज, उर्वरक, कीट नियंत्रण दवाओं की आपूर्ति करने वाले बहुराष्ट्रीय उद्योग कृषि प्रधान विकासशील और अल्प विकसित देशों को लक्षित करने में रुचि रखते हैं।

इसके अलावा लगभग 8 से 10 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बाजार में केला, भूलभुलैया, कॉफी, कोको, चावल और अन्य कृषि उत्पादों को नियंत्रित करती हैं और कीमतें निर्धारित करती हैं।

भारत, जहां विशाल कृषि व्यवसाय है, उनकी विशेष रुचि है। इसलिए यह खाद्य उद्योग, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय और बड़े व्यवसाय द्वारा लाभ का लक्ष्य है।

आजादी के शुरुआती दिनों में भारतीय किसानों ने जमीन के बंटवारे के लिए जमींदारों और बड़े जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया। 'जोतने वाले को भूमि' एक लोकप्रिय नारा था और कई राज्य सरकारों, विशेष रूप से केरल और पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने भूमि वितरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया। कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली किसान सभा इस माँग को उठाने में बहुत आगे थी। अधिकांश राज्यों में धीरे–धीरे लेकिन निश्चित रूप से सामंती स्वामित्व समाप्त हुआ। हालाँकि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के परिणामस्वरूप एक नए अमीर किसान वर्ग का उदय हुआ जो व्यवसायिक खेती कर रहा था।

हालाँकि, 1966 के अकाल ने एक राष्ट्र के रूप में भारत की कमजोरी और भोजन के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता को उजागर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त खाद्य की रणनीति तैयार हुई। नए संकर बीजों, सिंचाई सुविधाओं और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से किसानों की मदद से हरित क्रांति सफल हुई और भारत न केवल आत्मनिर्भर बन गया, बल्कि अनाज का निर्यातक भी बन गया।

इसमें सरकार की भूमिका के महत्व पर जोर देने की जरूरत है क्योंकि वर्तमान में इसे कमजोर करने और निजीकरण को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति जारी है।

एमएसपी और मंडियों को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका भी याद रखनी होगी। इसलिए अब 1995 के डब्ल्यूटीओ गठन के बाद, बड़े भारतीय एकाधिकार के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएसपी को लक्षित कर रही हैं और प्रतिस्पर्धा के नाम पर मंडियों के निजीकरण पर जोर दे रही हैं।

किसान, विशेष रूप से पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से इन डिजाइनों के बारे में जानते हैं और अब तक एमएसपी और मंडियों की भूमिका को खत्म करने के कदम का विरोध कर चुके हैं और इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय कृषि पर कब्जा करने की सुविधा के लिए कृषि कानून लाने के भाजपा सरकार के कदम के खिलाफ लड़े हैं। लेकिन ग्यारह महीने से अधिक समय तक किसानों के संघर्ष ने सरकार के इस प्रयास को विफल कर दिया था।

लडाई जीत ली गयी है परंतु युद्ध अभी भी बाकि है।

भाजपा सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों का अनुभव उनकी उम्मीद के विपरीत है। यह घोषणा की गई कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ है। इसके विपरीत इनपुट की कीमतों में वृद्धि के कारण उनकी आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हालांकि एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह कानून नहीं बना है और इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा की है कि लोगों को राशन की जगह नकद सब्सिडी दी जाएगी। इससे स्पष्ट खतरा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके लिए एमएसपी महत्वपूर्ण है, खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए, किसान संगठन अपना संघर्ष जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लड़ने वाली ट्रेड यूनियन इस लड़ाई में किसानों के साथ खड़ी हैं।

चीन को छोड़कर विश्व की दृष्टि कृषि उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों के प्रभुत्व की है। किसानों की जरूरत तो है लेकिन मालिक के रूप में नहीं बल्कि केवल मजदूर या विक्रेता के रूप में। चूंकि हमारी साठ प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि और संबंधित उद्योग पर निर्भर है, इसलिए यह नीति विनाशकारी होगी। हमें एक अलग नीति की आवश्यकता है जिसमें किसानों की स्वतंत्रता और भूमि और उत्पादों पर उनका नियंत्रण सुरक्षित बना रहे रहे। इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करना आवश्यक है। सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पूंजी हितों के अधीन रहने वाली वर्तमान भाजपा सरकार से भारतीय किसानों की रक्षा की यह भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए 2024 में बीजेपी को हराना किसानों और मजदूरों के हित में जरूरी हो जाता है।

शिक्षा के मानवीयकरण के संबंध में

भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए वैकल्पिक विजन और रणनीति

''विश्वविद्यालय मानवतावाद का, सहिष्णुता का, तर्क का, विचार के साहस का और सत्य की तलाश का प्रतीक होता है। वह मानव–नस्ल के लिए और भी उच्चतर उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ने का समर्थन करता है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का प्रर्याप्त रूप से निर्वाह करें तो वह राष्ट्र और जनता के हित में होगा।''– जवाहरलाल नेहरू

बिनोय विश्वम

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका मानविकी और विज्ञान के क्षेत्र में जबर्दस्त योगदान का इतिहास है। उच्चतर शिक्षा हमारे देश में आज भी चंद लोगों को ही मिल पाती है। उच्चतर शिक्षा में कुल भर्ती अनुपात 27.4 प्रतिशत है। यदि हम विकास करना चाहते हैं तो यह इससे काफी अधिक होना चाहिए। दुर्भाग्य से ''विश्व गुरू'' द्वारा लंबे–चौड़े दावों के बावजूद आज शिक्षा, विशेष तौर पर सरकारी शिक्षण संस्थानों की भारी उपेक्षा की जा रही है। ढांचा, मुद्दों और एकेडेमिक स्पेस सिकुड़ते जाने के दोहरे संकट से शिक्षण संस्थानों एवं अन्य अनेक संस्थानों का आगे का विकास बाधित हो रहा है।

सार्वजनिक शिक्षा का ढांचागत संकट सरकार द्वारा सौतेले बर्ताव का परिणाम है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा आम भलाई के लिए होनी चाहिए और हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए। एक तरफ निजी संस्थानों को अनगिनत फायदे पहुंचाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ, सार्वजनिक शिक्षा के लिए पैसा कम कर दिया जा रहा है। जिस सार्वजनिक शिक्षा ने भारत को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया वह आज इस साजिश का शिकार है कि शिक्षा केवल उन्हीं को मिले जो इसके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। जो सार्वजनिक शिक्षा हाशिये पर पड़े लोगों का शिक्षा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और देश के आम उत्थान में मदद करती है

वह आज इस साजिश का नतीजा भुगत रही है। आज कुल कॉलेज भर्तियों में 45 प्रतिशत भर्तियां निजी गैर–सहायताप्राप्त कॉलेजों और 21प्रतिशत में निजी सहायताप्राप्त कॉलेजों में होती है। व्यवसायिक कोर्सो के 72.5 प्रतिशत छात्र निजी क्षेत्र में हैं।

दूसरी बात यह है कि आज एकेडेमिक स्वतंत्रता विचारधारात्मक सेंसर का शिकार है। राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ एकाशात्मकता का विचार तर्क–वितर्क, विचार–विमर्श एवं संवाद के पूरी तरह खिलाफ है। अतीत के साथ आरएसएस की लगतार लड़ाई का नतीजा इतिहास के पुनर्लेखन और शिक्षा को अवैज्ञानिक बनाए जाने के तौर पर निकल रहा है। जो भी बात कुछ भिन्न, आलोचनात्मक या विविधतापूर्ण है उसके प्रति शून्य–सहिष्णुता विश्वविद्यालय परिसरों की जीवन्तता को खत्म करने पर लक्षित है।

सरकारी रिकॉर्डों के अनुसार, हर दूसरे महीने किसी न किसी आईआईटी का एक छात्र आत्महत्या कर लेता है। संस्थानों के अनुसार, एकेडेमिक दबाव इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। परंतु वास्तविकता यह है कि जो छात्र अत्यंत कठिन प्रतिस्पर्धा की परीक्षा देकर इन संस्थानों में दाखिल होते हैं, उन्हें वहां मानवीय मूल्यों के अभाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षा भावी पीढ़ियों के लिए मानवता की बेहतरीन विरासत प्रदान करने का एक साधन है परंतु अब वह शोषण एवं विलगाव तंत्र के लिए गरारियां बनाने का काम कर रही है।

सत्य और वैज्ञानिक जांच–पड़ताल की भावना पर भारी हमला हो रहा है। 20 जुलाई 2023 को जब मैंने संसद में प्रेस ब्यूरो इनफोर्मेशन की फैक्ट चैकिंग यूनिट के संबंध में एक प्रश्न पूछा तो संबंधित मंत्री ने एक टालू किस्म का जवाब दिया। यह स्पष्ट है कि किसी चीज की सच्चाई तय करने के लिए न तो कोई अपील का मंच है, न कोई संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ है और न कोई स्वतंत्र सदस्य हैं। सच और सरकारी प्रचार के बीच जो कशमकश है उसमें सरकार ही सच की एकमात्र पंच बन जाती है।

खेत मजदूर यूनियन के होने वाले 14वें राज्य सम्मेलन की तैयारियां

सोनभद्र में कैमूर विश्वविद्यालय की मांग के साथ होगा सम्मेलन

रेनूकुटः नगर स्थित हिंडाल्को प्रगतिशील मजदूर सभा के यूनियन कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कौंसिल व उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक सोनभद्र में होने वाले खेत मजदूर यूनियन के चौदहवें राज्य सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता लल्लन राय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जहां उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश महामंत्री फूलचंद्र यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश विषम परिस्थितियों की दौर में चल रहा है। हर जगह नफरत की राजनीति की जा रही है, देश के अंदर अपराध चरम सीमा पर है बहू, बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं सड़कों पर खुला तांडव मचाया जा रहा है मणिपुर का घटनाक्रम इसका सीधा उदाहरण हैं। जिस शर्मसार करने वाली घटना की हम निंदा करते हैं। पूरे देश में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई तेज हो गई है। देश की स्थिति बद से बद्तर होती जा रही है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सत्तासीन भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति पर सत्ता पर काबिज होने के फिराक में लगी हुई है। ऐसे में हम कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंगठनों के लोगों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया है कि चार राज्यों की सीमाओं को समेटे इस आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र में यूनियन का चौदहवां राज्य सम्मेलन कराया जाएगा। जहां जल, जंगल,जमीन को बचाने के लिए इसके साथ यहां शोषित पीड़ित और वंचितों को मुख्य धारा में जोड़ने के

लिए जनपद में एक अदद केंद्रीय कैमूर विश्वविद्यालय की स्थापना कराने के लिए ही खेत मजदूर यूनियन का चौदहवां राज्य सम्मेलन कराने का निर्णय किया गया है। बैठक में इस दौरान तीन दिवसीय 1–3 अक्टूबर को होने वाले यूनियन के राज्य सम्मेलन को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए लल्लन राय के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कमेटियों का भी गठन किया गया और सबकी जिम्मेदारी तय की गयी। बैठक में प्रमुख रूप से लालता प्रसाद तिवारी, पशुपतिनाथ विश्वकर्मा, प्रदीप कन्नौजिया, बुद्धि राम, अमरनाथ सूर्य, लता सिंह, देव कुमार विश्वकर्मा, मुन्नी लाल दिनकर, दूर्गा प्रसाद, सी. पी. माली, ज्योति रावत, कन्हैया लाल, राजेन्द्र प्रसाद, के के सिंह सहित दर्जनों की संख्या में अन्य उपस्थित रहे। बैठक का संचालन भाकपा जिला सचिव आर के शर्मा ने किया।

किसानों ने मागों के लिए दिया ज्ञापन

मवाना (मेरठ, उप्र), 24 जुलाई 2023: उत्तर प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने किसान सभा के जिलाध्यक्ष श्री संग्राम सिंह जी के नेतृत्व में 16 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम तहसीलदार मवाना सुश्री आकांक्षा जोशी को सौंपा

जिसमें किसान सभा के मंडलीय सचिव जितेंद्र पाल सिंह जी ने बताया कि मुजफ्फरनगर सीमा मेरठ जिले की तहसील मवाना के निम्नलिखित ग्राम राठौड़ा फतेहपुर भी कुंड शेरपुर, हंसापुर, परसापुर, हाथीपुर गांवड़ी, किशनपुर दूधली बस थोड़ा मखदुमपुर

लतीफपुर तारापुर किशोरपुर प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका का दंश झेलते हैं। जिसके चलते सभी ग्रामवासियों की फसलें जलमग्न होने से सड़ जाती हैं और उनके समक्ष जीविका का संकट प्रतिवर्ष खड़ा होता है। उन्हें शासन प्रशासन से कोई सहयोग सरकार की घोषणा के उपरांत नहीं मिल पाती है प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की फसलों में और मनुष्यों में बीमारियों का प्रकोप होता है। स्वास्थ्य विभाग भी उनकी सुध नहीं लेता है और नष्ट हुई फसलों की भरपाई के लिए वे बीमा कंपनियों और शासन ने कोई कार्रवाई पिछले 10 वर्षो से ग्राम वासियों के लिए नहीं की है। जबकि इन सभी ग्राम वासियों को प्रतिवर्ष बर्बादी से बचाने हेतु बांध बनाना अति आवश्यक है।

ज्ञापन में कहा गया कि किसानों की लंबी मांगों के उपरांत सरकार द्वारा बिजली बिलों को माफ करने की घोषणा की गई है। जिसमें घोषणा करते समय शर्त लगाई गई थी जो किसान 31 मार्च 2023 तक का समस्त बिल जमा करेगा और अपनी ट्यूबवेल पर मीटर लगवाएगा उस किसान को 31 मार्च 2023 के बाद से ट्यूबवेल के बिल की माफी का लाभ मिलेगा। साथ ही कहा गया कि ऐसे किसी किसान को बिल माफी का लाभ नहीं मिलेगा जो पिछला बिल अदा नहीं करेगा या जो बिजली विभाग का बकायेदार होगा। अब ट्यूबवेल के बिल माफी की घोषणा के उपरांत विद्युत विभाग अनाप–शनाप बिजली बिल भेज रहा है जिससे कनेक्शन धारी किसान उलझन में है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है। अधिकारियों से मुलाकात के उपरांत जानकारी प्राप्त हुई कि सरकार का ऐसा आदेश अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ है कि किसानों के बिल माफ किए जाएं सिर्फ हमारे पास आदेश है कि ट्यूबवेल पर अभिलंब मीटर लगाए जाएं।

किसान सभा उपरोक्त संबंध में आपसे मांग करती है कि:

1 सभी किसानों के पिछले व आगामी समस्त बिल माफ करें

2 किसानों की ट्यूबवेल पर मीटर ना लगाई जाएं

3 किसानों की ट्यूबवेल को श्रेणी में ना बांटा जाए

4 बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण रोका जाए

5 गंगा क्षेत्र में मुजफ्फरनगर, मेरठ सीमा से उपरोक्त ग्रामों तक पक्का बांध बनाया जाए और बाढ़ से नष्ट हुई फसलों का सरकार मुआवजा दें

6 बाढ़ से नष्ट हुए चारे के संबंध में सरकार पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करें स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां भेजी जाएं

इस मौके पर किसान नेता जितेंद्र पाल सिंह, राजपाल शर्मा, संग्राम सिंह, बिल्लू चौधरी, नरेश तोमर, ठाकुर भंवर सिंह, ठाकुर कमल सिंह, जगदीश रणबीर कुलदीप रामवीर सिंह व दर्जनों किसान उपस्थित रहे।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दरः

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रूपये

खाता नामः **मुक्ति संघर्ष वीकली**
बैंकः **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्याः **1033004704**
आईएफसी कोडः **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखें:
व्यवस्थापकः मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोटः डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक'' के नाम होना चाहिए।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

आर.एस. यादव

मणिपुर में हैवानियत

20 जुलाई 2023 को सोशल मीडिया पर एक ऐसा विडियो प्रसारित हुआ जिसमें बहुत सारे लोग दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमा रहे हैं। उनके साथ छेड़खानी की कोशिश दिख रही है। यह घटना 4 मई की बताई जा रही है यानी 3 मई को हिंसा शुरू होने से दूसरे दिन यह घटना हुई। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि करीब एक हजार लोगों की हथियारबंद भीड़ उनके गांव में घुस आई और आगजनी और कत्लो–गारत शुरू कर दिया। पुलिस उन दोनों महिलाओं को अपनी गाड़ी में थाने ले जा रही थी तभी भीड़ सामने आ गई और पुलिस उन्हें भीड़ के बीच गाड़ी से उतार कर चली गई। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। सारी घटना पुलिस की जानकारी में और उनके सामने हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह 2002 में गुजरात में पुलिस की मौजदूगी में हर तरह की दरिन्दगी की गई और पुलिस देखती रही।

द इंडियन एक्सप्रेस (21 जुलाई 2023) की रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर में कुकी–जोमी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने और यौन उत्पीड़ित किए जाने के विडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद उनमें से एक पीड़िता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें ''पुलिस ने भीड़ के बीच छोड़ा था''। 4 मई के विडियो में एक महिला 20 वर्ष के आसपास और दूसरी 40 वर्ष और भीड़ द्वारा उन्हें निर्वस्त्र कर परेड कराते हुए देखा जा सकता हैं। कुछ लोग उन दो महिलाओं को एक खेत की तरफ खींचते और उनके साथ नोचा–खोची करते देखे जा सकते हैं। एक पुलिस शिकायत में, जिसे पीड़ितों ने 18 मई को दर्ज कराया था, उन्होंने आरोप लगाया कि उनमें से युवा महिला के साथ ''दिन–दहाड़े नृशंसतापूर्वक बलात्कार किया गया''।

शिकायत में उन्होंने कहा कि जब कांगपोकपी जिले में उनके गांव पर एक भीड़ ने हमला किया तो वे बच निकलने के लिए जंगल की तरफ दौड़कर चली गई और थोबल पुलिस ने उन्हें वहां से बचाकर निकाला।

शिकायत में कहा गया है कि पुलिस उन्हें थाने की तरफ लेकर जा रही थी परंतु एक भीड़ ने बीच रास्ते रोक लिया और उसके गंतव्य से लगभग दो किलोमीटर पहले पुलिस हिरासत से उन्हें छीन लिया।

परंतु युवा महिला ने अपने पति के घर से फोन पर बोलते हुए आरोप लगायाः ''पुलिस उस भीड़ के साथ थी जो हमारे गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस ने हमें घर के पास से उठाया, हमें गांव से कुछ दूर ले गई और फिर हमें भीड़ के पास सड़क पर छोड़ दिया। हमें पुलिस ने भीड़ के हवाले किया था''।

अपनी शिकायत में पीड़ितों ने कहा है कि वे पांच महिलाएं एक साथ थीः विडियो में दो महिलाएं दिखाई पड़ती हैं, एक अन्य महिला जो 50 वर्ष से अधिक रही होगी, उसे भी कथित तौर पर निर्वस्त्र किया गया और युवा महिला के पिता और भाई की भीड़ ने हत्या कर दी। उसने कहा, ''पुरूषों की हत्या करने के बाद उन्होंने जो कुछ किया, वह किया, फिर हमें वहीं छोड़ दिया, और वहां से चले गए''।

इस घटना पर जब मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी सैंकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। यह प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसी दादरी में तथाकथित गौरक्षकों (जो आरएसएस समर्थित लोग होते हैं) लोगों द्वारा मोहम्मद अखलाक को ''लिचिंग''किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। पत्रकार तवलीन सिंह ने लिखा है कि जब ''यह ''लिचिंग'' हुई थी 2016 में, मैं उनसे मिलने गई थी अपनी नई किताब उनको देने और मैंने पूछा था कि मोहम्मद अखलाक की गोरक्षकों द्वारा ''लिचिंग'' की निंदा क्यों नहीं करते हैं, तो उनका जवाब था कि कुछ न कुछ रोज होता है इस देश में, तो उनको निंदा करने से किसी और काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी'' (इंसानियत पर धब्बा, तवलीन सिंह, जनसत्ता, 23 जुलाई 2023)।

3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है। लोग मर रहे है। कानून का शासन वहां खत्म है। लगातार कत्लो–गारत चल रहा है। मणिपुर में तथाकथित ''डबल इंजन की सरकार'' है। एक इंजन का नाम है नरेन्द्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं और दूसरे इंजन का नाम है बीरेन सिंह जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की यह सरकार मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम है और लगातार हिंसा का दौरदौरा चल रहा है। इसके लिए डबल इंजन की सरकार के अलावा कौन जिम्मेदार है? इस डबल इंजनों के अलावा मणिपुर की भयानक स्थिति के लिए अन्य कौन जिम्मेदार है? दुनिया स्तब्ध है कि दो महीने से अधिक समय से मणिपुर जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, लोग मर रहे हैं, राज्य में हाहाकार मचा है और प्रधानमंत्री के मुंह से उसके संबंध में एक शब्द भी नहीं निकला।

दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का विडियो सामने आया तो प्रधानमंत्री की खामोशी टूटी। उन्होंने इस घटना पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पीड़ा से मेरा मन भर गया है। गुनाह करने वाले कितने और कौन हैं, पर बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कानून अपनी पूरी शक्ति और सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएंगी। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में राजनीति और वाद–विवाद से ऊपर उठकर कानून–व्यवस्था का महात्मय और नारी का सम्मान है। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा।

देशवासी प्रधानमंत्री का विश्वास कैसे कर सकते हैं? दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने, उनका बलात्कार करने और हत्या का मामला 4 मई को हुआ था, प्रधानमंत्री को इसकी पीड़ा सोशल मीडिया पर विडियो आने के बाद 20 जुलाई को ही क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं? प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री होने के नाते वहां की पल–पल की घटना, पल–पल की जानकारी उन्हें अवश्य ही मिलती रही है। इस मामले की एफआईआर तो बहुत पहले ही दर्ज हो चुकी थी। देश के लोगों को तो अवश्य ही इसकी जानकारी 20 जुलाई को सोशल मीडिया पर विडियो आने के बाद ही हुई, परंतु मणिपुर के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं कह सकते कि वे अब तक इस घटना के बारे में नहीं जानते थे।

चार मई को थोबल में महिलाओं के साथ भीड़ ने दरिन्दगी की। इसका विडियो बनाया। कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया। 18 मई को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। 21 जून को एफआईआर दर्ज हुई। 19 जुलाई को विडियो सोशल मीडिया पर आया। जनता को तो इससे पहले मालूम नहीं था कि मणिपुर में इस तरह की हैवानियत हो रही है परंतु मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री को तो सब कुछ मालूम था। प्रधानमंत्री को इसकी पीड़ा दो महीने से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद 20 जुलाई को ही क्यों हुई, पहले क्यों नहीं? क्या इसलिए कि सारी दुनिया को भारत के एक राज्य में हो रही इस घटना की खबर मिल गई और प्रधानमंत्री के लिए यह जरूरी हो गया कि इस पर दुख जाहिर करें? या इसलिए कि सोशल मीडिया पर प्रसारित विडियो का स्वतःसंज्ञान लेते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 20 जुलाई को नाराजगी भरे लहजे में कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे, अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे?

प्रधानमंत्री के इस कथन पर कौन विश्वास करेगा कि मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कीस बानो तो गुजरात की बेटी है, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके परिवार के कोई दर्जन भर लोग मार डाले गए। उसके गुनाहगारों को नरेन्द्र मोदी के मुख्य मन्त्रित्व में भाजपा की गुजरात सरकार ने लगातार बचाने की कोशिश की, यहां तक कि उस मामले में यह समझ कर कि गुजरात में मुल्जिमों पर मुकदमा ठीक से नहीं चल सकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंबई में सुनवाई किए जाने का आदेश दिया था। अदालत से मुल्जिमों को सजा भी मिल गई परंतु केंद्र सरकार के सहयोग और सलाह–मशविरे के साथ गुजरात सरकार ने बिल्कीस बानो के साथ हैवानियत करने वालों को सजा पूरी होने से पहले जेल से रिहा कर दिया। प्रधानमंत्री की पार्टी और आर.एस.एस. के लोगों ने उनकी रिहाई के बाद उनका स्वागत किया। जिस प्रधानमंत्री ने गुजरात की बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि मणिपुर की बेटियों के साथ इंसाफ करेंगे?

हाल ही में, देश ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं में भारत का गौरव बढ़ाने वाली, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाने वाली हरियाणा की बेटियों ने जब आरोप लगाया कि भाजपा के संसद सदस्य ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ यौन अपराध किया है तो प्रधानमंत्री ने उस पर गौर ही नहीं किया। वे ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर–मंतर पर धरने पर बैठी तो भी भाजपा संसद सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी गई। उसके खिलाफ एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हो सकी। जिस प्रधानमंत्री ने हरियाणा की बेटियों के दर्द को ही नहीं समझा वह मणिपुर के बेटियों के दर्द को क्या समझेंगे?

मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

प्रधानमंत्री मोदी ने मानो कसम ही खा ली है कि वह मणिपुर के संबंध में संसद में कुछ भी नहीं बोलेंगे। वैसे तो उन्होंने मणिपुर की घटनाओं के संबंध में पहले ही चुप्पी साध रखी थी और 3 मई से मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा और कानून एव व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने के बावजूद 20 जुलाई तक उनकी चुप्पी कायम रही। 19 जुलाई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने एवं बलात्कार की घटना जब सोशल मीडिया पर आई और भारत क्या, तमाम दुनिया उस हैवानियत को देखकर स्तब्ध हो गई और हर कहीं थू–थू होने लगी, तब जाकर प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी और उन्होंने उस पर अफसोस जाहिर किया।

19 जुलाई से भारत की संसद चल रही है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य था कि संसद में आकर इस शर्मनाक घटना अफसोस जाहिर करते और मणिपुर में हालात में सुधार लाने के लिए कोई गंभीर कार्रवाई करने का वायदा करते। परंतु संसद से वह लगातार बचते ही रहे। प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी भी संसद से बाहर छोड़ी। मालूम नहीं उन्हें संसद में आने और मणिपुर की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने में क्या डर लग रहा है?

संसद में विपक्ष ने लगातार मांग उठाई कि सब काम छोड़कर सबसे पहले मणिपुर के भयानक हालात पर चर्चा की जाए। परंतु सरकारी पक्ष तुला हुआ है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं करने देंगे। अंततः मणिपुर पर चर्चा करने के लिए सरकार को विवश करने के लिए विपक्षी गठबंधन ''इंडिया'' की ओर से 26 जुलाई 2023 को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। शीघ्र ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ेगा।

14.5 6 लाख करोड़ रुपए डाले गए बट्टेखाते में

मोदी राज में पूंजीपति वर्ग के मजे ही मजे है, बैंकों से कर्ज लेते हैं, उनमें से कई मूलधन का भुगतान करते हैं न उसके ब्याज का, और सरकार उनके कर्ज को बट्टेखाते में डाल देती है और फिर उन्हें बैंक से आगे भी कर्ज मिलता रहता है। बट्टेखाते में डाले गए इस पैसे का अंततः नुकसान आम जनता का ही होता है क्योंकि इस पैसे को किसी न किसी तिकड़म से आम जनता से ही वसूल किया जाता है। इसका प्रकारान्तर में अर्थ है कि कर्ज

शेष पेज 6 पर...

कुछ सामयिक मुद्दे एवं ...

पेज 5 से जारी...

पूंजीपति लेता है और भुगतान आम जनता करती है। इस तरह से पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर मोदी राज के नौ वर्षों में पूंजीपति वर्ग का कितना कर्ज बट्टेखाते में डाला गया है, इस अंधेरगर्दी को साल दर साल बट्टेखाते में जाने वाले रकम से समझा जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस (24 जुलाई 2023) को सूचना के अधिकार के कानून के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2012–13 से 2022–23 तक निम्न रकम बट्टेखाते में डाली गई:

वर्ष	बट्टेखाते में डाली गई रकम (करोड़ रुपए में)
2012–13	42.235
2013–14	32.992
2014–15	58.786
2015–16	70.413
2016–17	108.373
2017–18	161.328
2018–19	236.265
2019–20	234.170
2020–21	202.781
2021–22	174.966
2022–23	209.144

इस प्रकार मोदी सरकार के पिछले नौ सालों में 14.557 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों द्वारा बैंकों से लिया गया कर्ज बट्टेखाते में डाल दिया गया है।

बैंकों नियमों के अनुसार जब किसी मूल धन या उसके ब्याज का भुगतान देय–तिथि से 90 दिन बाद भी नहीं होता और बैंक समझता है कि इस पैसे की वसूली होने की उम्मीद नहीं है तो उसे एनपीए कहा जाता है।

लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए सरकार यह दावा भी करती है कि मार्च 2023 में एनपीए घटकर कुल अग्रिम (यानी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों) का 3.9 प्रतिशत हो गया है जो पिछले दस सालों में सबसे कम है।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वित्तवर्ष 2018में बैंकों का कुल एनपीए10.21 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2023 में घटकर 5.5 लाख करोड़ रुपए रह गया। एनपीए में यह कमी इसकी वसूली से नहीं आई बल्कि इसके बट्टेखाते में डाल जाने से आई। इस तिकड़म से बैंकों का एनपीए घटकर कुल अग्रिम (यानी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों) का 3.9 प्रतिशत हो गया है और इसे सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है।

उल्लेखनीय है कि इस कर्ज को बट्टेखाते में डाल दिया जाता है तो फिर उसे एनपीए में शामिल नहीं किया जाता। यदि पूरे के पूरे एनपीए को बट्टेखाते में डाल दिया जाए तो बैंकों का बकाया एनपीए शून्य रह जाएगा; क्या इस तरह बैंकों के एनपीए को शून्य किए जाने को एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा सकता है?

यह भी उल्लेखनीय है कि पैसे को बट्टेखाते में डालने के बाद भी बैंक नियमों के अनुसार, ऐसा पैसा माना जाता है जो बैंक को वापस नहीं मिल पाया है और बैंक इस पैसे को वापस वसूल करने की कोशिश जारी रखेगा। पर यह कोशिश कितनी कामयाब होती है इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि पिछले तीन सालों में 5.87 लाख करोड़ रुपए के एनपीए को बट्टेखाते में डाला गया है परंतु इन कोशिशों के जरिये इसमें से केवल 1.09 लाख करोड़ रुपए को ही वसूल किया जा सका।

मजे की बात यह है कि जिन पूंजीपतियों द्वारा लिए गए ऋणों को बट्टेखाते में डाला जाता है उनके नाम जाहिर नहीं किए जाते। नाम जाहिर करने पर बाजार में उनकी साख गिरने की संभावना हो जाती है और अन्य बैंक भी उन्हें कर्ज देने से कतरा सकते हैं। सरकार उन्हें इस समस्या और बदनामी से भी बचाकर रखती है।

क्या यह संभव नहीं है कि जिन पूंजीपतियों पर बैंकों के सैंकड़ों या हजारों करोड़ रुपए बकाया हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और जब तक भुगतान न करें, उन्हें जेल में ही रखा जाए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के मालिक सुव्रत रॉय के साथ किया था जिनके ऊपर आम जनता के करोड़ों रुपए बकाया थे? जेल में डाले जाने के बाद सुव्रत रॉय ने पैसे का इंतजाम किया, इसके लिए अपनी संपत्तियां बेची और पैसे का भुगतान किया। क्या यही सलूक बैंकों से कर्ज लेकर वापस उसका भुगतान न करने वाले पूंजीपतियों के साथ नहीं किया जाना चाहिए? यदि ऐसी कार्रवाई करने के लिए कोई कानून नहीं है तो क्या इस तरह का कानून बनाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए?

पिछले वित्त वर्ष में बंद हुए 13, 299 उद्योग

20 जुलाई 2023 को सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि जुलाई 2020 से मार्च 2023 तक करीब तीन वर्षों में देश में 19,687 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए या उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक 175 सूक्ष्म, उद्यम लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए या उन्होंने काम करना बंद कर दिया।

अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 6,222 सूक्ष्म, उद्यम लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए या उन्होंने काम करना बंद कर दिया।

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक अर्थात पिछले वित्त वर्ष में 13,290 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बंद हो गए या उन्होंने काम करना बंद कर दिया।

इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि सूक्ष्म, उद्यम लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां संकट से गुजर रही हैं जो 2016 में नोटबंदी के साथ शुरू हुआ था। इन आंकड़ों पर बारीकी से नजर डालें तो समझा जा सकता है कि उद्योग इससे कहीं अधिक बड़ी संख्या में बंद हुए हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक 175 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए या उन्होंने काम करना बंद कर दिया। यह समय था जब कोरोना महामारी का प्रकोप अपने चरम पर था और जिस दौरान महीनों तक लॉकआउट भी रहा जिसके दौरान सभी छोटे–बड़े उद्योग–धंधे और कारोबार चौपट थे। ऐसे में कैसे यकीन किया जा सकता है कि इस दौरान केवल 175 सूक्ष्म उद्यम लघु और मध्यम उद्यम बंद हो हुए? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद होने का अर्थ है कि बड़ी संख्या में वे लोग बेरोजगार हो गए जो इनमें काम करते थे। इससे देश में बढ़ती बेरोजगारी का भी संकेत मिलता है।

आत्मनिर्भरता का सरकार का दावा

अकसर प्रचार किया जाता है कि मोदी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। वास्तविकता इससे विपरीत है। उदाहरणार्थ, 2013–14 में भारत अपनी तेल की जरूरत के 77 प्रतिशत के लिए आयातित कच्चे तेल पर निर्भर करता था, 2022 (अप्रैल–जून 2023) में यह निर्भरता बढ़कर 88.3 प्रतिशत हो गई है। सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 2022 तक आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को घटाकर 67 प्रतिशत पर लाया जाएगा। परंतु कच्चे तेल पर निर्भरता घटने के बजाय बढ़कर 88.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। कच्चे तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इसकी मांग बढ़ रही है और घरेलू उत्पादन ठहराव का शिकार है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश के कुल आयात में भारी वृद्धि हुई है जो इस बात का संकेतक है कि आयात पर निर्भरता में वृद्धि हो रही है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30 प्रतिशत से अधिक पद खाली

सरकार उच्च शिक्षा की किस तरह उपेक्षा करती है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पद इसका ज्वलंत उदाहरण है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 18,956 है जिसमें से लगभग एक–तिहाई (6,028) पद खाली पड़े हैं। उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 88 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। जम्मू एवं कश्मीर और त्रिपुरा के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 50 प्रतिशत से अधिक पद खाली पड़े हैं।

आंध्रप्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी, में एक भी शिक्षक नहीं हैं, शत–प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार सफाई देते हैं कि नए विश्वविद्यालय को पूरी तरह फंक्शनल करने के लिए आम तौर पर तीन से पांच साल लग जाते हैं। ऐसे नए विश्वविद्यालयों में अन्य विश्वविद्यालय से शिक्षक लाकर शिक्षण कार्य किया जाता है। उनकी इस सफाई को संतोषजनक नहीं माना जा सकता है।

उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 88 प्रतिशत, त्रिपुरा विश्वविद्यालय में 50.3 प्रतिशत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 45 प्रतिशत, डॉ. हरीसिंह गौड विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश में 63 प्रतिशत, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 60.5 प्रतिशत, दिल्ली विश्वविद्यालय में 46.50 प्रतिशत, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय 46.6 प्रतिशत, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय 42.7 प्रतिशत और नार्थ–ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय में 42.3 प्रतिशत पद खाली पड़े है। जिन विश्वविद्यालयों में इतनी बड़ी मात्रा में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं उनमें शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले, इसकी आशा भी नहीं की जा सकती।

विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों पर आरक्षण के नियम लागू होते हैं। खाली पड़े पदों में बड़ी संख्या आरक्षित पदों की है। सामान्य पदों में 20 प्रतिशत शिक्षक पद खाली हैं। परंतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद 38 प्रतिशत, अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षित पद 44 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद 45 प्रतिशत, शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए आरक्षित पद 58 प्रतिशत और आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए आरक्षित पद 71 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।

उपरोक्त जानकारी उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत दी गई है। (साभार, द हिन्दू, 20 जुलाई 2023)

निजीकरण का शिक्षापरा दुष्प्रभाव

निजीकरण का शिक्षा पर सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह पड़ा है कि शिक्षा, विशेषकर उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर होती चली जा रही है। वित्तीय सेवाओं से जुड़े संस्थान ''बैंक बाजार'' द्वारा शिक्षा पर आने वाले खर्च के विश्लेषण के अनुसार, देश में महंगाई दर औसतन 6 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि शिक्षा पर आना वाला खर्च 11 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। यानी उच्च शिक्षा महंगाई दर से दोगुनी रफ्तार से महंगी हो रही है। उदाहरण के लिए, 2003 में भारत में निजी कॉलेज से एमबीए करने पर औसतन 3 लाख रुपए खर्च आता था जबकि मौजूदा समय में 24.6 लाख रु. खर्च हो रहे हैं। इसी रफ्तार से शिक्षा महंगी होती गई तो अगले पांच साल में एमबीए या अन्य प्रोफेशनल कोर्स का खर्च लगभग दोगुना हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में बीटेक के चार साल के कोर्स में औसतन 10 लाख रुपए का खर्च पड़ता है जबकि निजी कॉलेजों में एमबीबीएस का औसतन खर्च 50 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अगले पांच साल में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहेंगे तो यही खर्च एक करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। असल में तो कई निजी कॉलेजों में यह खर्च अब भी एक करोड़ से रुपए से कम नहीं है।

जाहिर है निजीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा, विशेषकर उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा को आम आदमी तो क्या मध्यम वर्ग के भी बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर कर दिया है। मध्यमवर्ग में कितने लोग हो सकते हैं जो अपने बच्चों को इतनी महंगी शिक्षा दिला सकें?

शिक्षा की तरह चिकित्सा भी इसी तरह अत्यधिक महंगी हो गई है। शिक्षा एवं निजीकरण की नीति आम एवं मध्यमवर्ग विरोधी ही नहीं, मानवविरोधी भी है।

चार संकाय सदस्य, छात्र निष्कासित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जनतंत्र पर खतरा

अरुण कुमार

साउथ–एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) एक अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसे सार्क (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग कोऑपरेशन) सदस्य देश प्रायोजित करते हैं। इन सदस्य देशों में हैं अफगानिस्तान, बंग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। एसएयू की स्थापना 2010 में स्थापित हुई थी। 2005 के नवंबर में ढाका में हई 13वें शिखर सम्मेलन में डॉ. मनमोहन सिंह के प्रस्ताव पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सार्क सदस्य देशों के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को विश्व सतरीय फैकल्टी मुहैया कराने के लिए की गई थी। एसएयू की स्थापना के लिए अन्तर–शासकीय समझौतों पर 14वें शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए और निर्णय लिया गया कि एसएयू की स्थापना भारत में होगी। एसएयू उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पड़ोसी सार्क देशों को जोड़ने के उच्च आदर्शों के साथ बनाई और स्थापित की गई थी।

लेकिन पिछले चार–पांच सालों से एसएयू कैम्पस कष्ट में है। शैक्षणिक माहौल गंभीर रूप से विकृत हो गया है जो कि सरकार की संरचना पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। छात्रों और अध्यापकों के जनतांत्रिक अधिकारों की अवहेलना की गई है अभिव्यक्ति के अधिकार, मतभेद के अधिकार को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया है। एसएयू प्रशासन हमेशा से ही शिक्षकों और छात्र समुदाय को धमकाने के लिए अस्वीकार्य और अन्यायपूर्ण काम कर रहा है।

कोविड–19 महामारी के बाद विश्वविद्यालय के फिर से खुलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन का शोषणकारी रवैया ध्यान में आने लगा। स्नाकोत्तर विभागों के छात्रों और शोधार्थी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों के मासिक स्टाइपेन्ड को बढ़ाने का अनुरोध किया था। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों के छात्रों और लगभग 15 से 20 फैकल्टी सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले के न्यायसंगत समाधान के लिए लिखा था।

स्टाइपेन्ड की राशि में विश्वविद्यालय द्वारा कटौती के बाद, छात्र कैम्पस में सितंबर 2021 में हड़ताल पर बैठे। लेकिन विश्वविद्यालय परिसर ने छात्रों को पीड़ित करने वाली समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और कई तरह से उनके प्रदर्शनों को दबाना शुरू कर दिया।

फैकल्टी सदस्यों ने छात्रों की न्यायसंगत मांगों को अपना नैतिक समर्थन दिया और एसएयू प्रशासन से विश्वविद्यालय के जनतांत्रिक नियमों को बनाए रखने की अपील की।

आखिर में छात्रों में एसएयू के परिसर में भूख–हड़ताल शुरू कर दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विरोध कर रहे छात्रों को निलंबित और निष्कासित करना शुरू कर दिया और आखिर में छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने और छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को बुलाया गया।

एसएयू के इतिहास में यह पहली बार था जब कैम्पस में छात्र प्रदर्शन के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को बुलाया था। आखिरकार छात्रों पर क्रूरता से लाठियां बरसाई गई। उनमें से कइयों को अकारण निलंबित किया गया और दूसरों को निष्कासित किया गया। यह बहुत चौंकाने वाला है कि निष्कासित छात्रों में से एक को दिल का दौरा पड़ने के बाद भी एसएयू प्रशासन का छात्रों के वाजिब मुद्दों पर दिल नहीं पसीजा।

कैम्पस के मामले में पुलिस को शामिल करना कुछ ऐसा था जिसने फैकल्टी सदस्यों को विक्षुब्ध किया। उन्होंने एसएयू प्राधिकारियों की छात्रों की दशा के प्रति उदासनीता की आलोचना करते हुए और छात्रों की वास्तविक मांगों का समर्थन करते हुए एक कड़ा पत्र लिखा। इस पत्र को एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया जिससे मामला और जटिल हो गया।

इन सब मामलों की छानबीन के लिए एक फैक्ट फाइडिंग कमेटी बनाई गई।

इस फैक्ट फाइडिंग कमेटी ने चुनिंदा लोगों को लक्षित करते हुए चार फैकल्टी सदस्यों को (एक सदस्य समाजशास्त्र से, दो अर्थशास्त्र से और एक कानून विभाग से) 19 मई 2023 को नाटिस दिया और कमेटी सदस्यों के सामने बैठकर 100 से ज्यादा सवालों के जवाब हस्तलिखित देने को कहा। फैकल्टी सदस्यों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति की और फैक्ट फाइडिंग कमेटी और एसएयू प्रशासन को लिखा लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके विपरीत इन फैकल्टी सदस्यों को 16 जून 2023 को ''छात्रों को और बाहरी व्यक्तियों'' को भड़काने और उनका नेतृत्व करने और उन्हें ''समाज–विरोधी कामों'' में शामिल करने का आरोप लगाते हुए निलंबन का नोटिस दिया।

उन पर छात्रों को मार्क्सवादी दर्शन पढ़ाने का आरोप भी लगाया गया, जो कि एसएयू के पाठ्यक्रम का भाग है। उन्होंने जांच की प्रक्रिया के बिना उन पर आरोप लगाया इस अवैधानिक और अजनतांत्रिक निलंबन नोटिस से आगे जाकर इन संकाय सदस्यों को बिना अनुमति के शहर छोड़कर न जाने का निर्देश दिया, उन्हें अपने कार्यालय को खाली करने, विभागीय कम्प्यूटर लौटाने, पहचान पत्र लौटाने और अपने संबंधित विभाग के संकायध्यक्ष के पास प्रत्येक कार्यदिवस की उपस्थिति भरने का निर्देश दिया गया।

एसएयू के संकाय सदस्यों की प्रशासन द्वारा इस तरह के अभूतपूर्व उत्पीड़न और धमकाने की घटनाओं का देशभर के अध्यापकों एवं छात्रों ने भर्त्सना की है। लेकिन अभी भी एसएयू से लगाातर निलबंन, और अन्ततः निष्कासन की खबरें मिल रही है।

निलबंन और निष्कासन के नोटिसों से छात्रों पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि चार संकाय सदस्यों के निलंबन से एसएयू प्रशासन उन सभी छात्रों एवं अध्यापकों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है जो भी प्रशासन के मनमानी, निरंकुश कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। एसएयू की कार्यवाही पूरी तरह अभिव्यक्ति के अधिकार, असहमति के अधिकार और विरोध के अधिकार के विरूद्ध है। एसएयू गवाह है धीरे–धीरे बढ़ते निरंकुशीकरण का जो कि उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण और भगवाकरण का अनिवार्य पूरक है।

वर्तमान भारत की केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी के दक्षिण–एशियाई चरित्र को अनिश्चित कर दिया है। फैक्ट फाइडिंग कमेटी रिपोर्ट प्रशासन के छिपे अजनतांत्रिक ऐजेन्डा से प्रेरित और मात्र छलावा थी, विश्वविद्यालय समुदाय के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए नियमों और अधिनियमों की मांग करने वाली जनतांत्रिक आवाजों के सभी प्रभावों को खत्म करने के लिए। प्रशासनिक अधिकारियों की अजनतांत्रिक कार्यवाही एक सूचक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के संचालन का जो कि हमारी छवि को खराब करता जा रहा है।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद से, लगभग सभी विश्वविद्यालय फंड की कमी, फैकल्टी सदस्यों की कमी, विश्वविद्यालय अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्रों समेत मजदूर वर्ग के जनतांत्रिक अधिकारों के उन्मूलन का सामना कर रहे हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद से यह कैम्पसों में रोज का मामला हो गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रतिकूल प्रभाव धीरे–धीरे उभर रहे हैं जो कि भारत की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं और कैम्पस की स्वायत्तता और जनतांत्रिक माहौल को खत्म कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया–मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय और कई अन्य जिसका सामना कर रहे हैं एसएयू का मामला उसी क्रम में से एक है। एआईएफयूसीटीओ, एफईडीसीयूटीए, जेएनयूटीए के अलावा जेएफएमई ने एसएयू प्रशासन द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों पर नियमों एवं अधिनियमों से परे अजनतांत्रिक कार्यवाहियों के खिलाफ अपना संताप और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर और सार्क अधिकारियों से इस मामले को देखने और अविलंब चार फैकल्टी सदस्यों के निलबन को वापिस लेने और असंतुष्ट छात्रों के निकाले जाने/निलंबन को रद्द करने और शीघ्रातिशीघ्र उनके साथ न्याय करने के लिए लिखा है।

भाकपा के सांसद बिनोय विश्वम सहित कई सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है और भारत के विदेश मंत्री और सार्क अध्यक्ष को इस मामले के समाधान और निपटारे के लिए पत्र लिखा है।

जवाब का इतंजार है। इस बीच देश भर के सभी अध्यापक संगठन अध्यापकों और छात्रों पर एसएयू प्रशासन के अजनतांत्रिक और घृणित कार्यवाहियों के खिलाफ राज्य स्तर पर विरोध करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम शिक्षा बचाओ, कैम्पस बचाओ, और राष्ट्र बचाओ के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंततः यह हमारा संविधान बचाओ, जनतंत्र बचाओ और राष्ट्र बचाओ के लिए संघर्ष है।

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से चार संकाय सदस्य और छात्रों के निष्कासन पर पटना में आयोजित की गई एक प्रतिरोध सभा

मणिपुर में हिंसा के खिलाफ भाकपा के विरोध की झलकियां

CPI ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സ്

मणिपुर में 80 दिनों से हो रही हिंसा सरकार तुरन्त रोको।
80 Days Manipur Violence must Stop by Goverment
सीपीआई महिला नेत्रियों पर हुई FIR तुरन्त रद्द हो।
Drop FIR on CPI Women Leaders
COMMUNIST PARTY OF INDIA
DELHI STATE COUNCIL

संयुक्त आम
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
जिला कौंसिल लखनऊ

கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

পঞ্চায়েতে ভোট লুঠ ও সন্ত্রাসকে ধিক্কার। এই মৃত্যুমিছিল চাই না
ভাঙড়ে গণহত্যার প্রতিবাদে
কেন্দ্রীয় প্রতিবাদ মিছিল
১৩ জুলাই ২০২৩

इनकलाब जिंदाबाद
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
जिला कौंसिल-सोनभद्र (उ.प्र.)

মণিপুরের অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে
অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী
বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ

बैंकों में लाये जा रहे बदलाव आमजन के नहीं, बल्कि कारपोरेट हित में

हरनाम सिंह

इंदौर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 54 वर्ष पूर्व 19 जुलाई 1969 को हुआ था। तब से अब तक बैंकों की कार्यप्रणाली एवं नीतियों में बड़े बदलाव आये हैं। उदारीकरण की नीतियाँ अपनाने के बाद 1991 से ही बैंकों को आम लोगों के बजाय बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुविधा और लाभ के लिहाज से बदला जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में जो बदलाव किये गए हैं, वे न केवल कारपोरेट क्षेत्र को खुलेआम मुनाफा पहुँचाने के उद्देश्य से किये गए हैं, बल्कि बैंकों को आमजन की लूट का एक औजार बना दिया गया है। नित नयी सरकारी योजनाओं का बोझ बैंकों पर बढ़ाया गया है लेकिन वहाँ नये कर्मचारियों की भर्ती ही नहीं की जा रही है। इससे बैंकों के आम उपभोक्ताओं और बैंकों के कर्मचारियों, दोनों पर ही दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज यह बहुत जरूरी है कि आम लोगों को बैंकों में आ रहे इन बदलावों को समझाया जाए और उन्हें जागरूक किया जाए।

ये विचार अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन (एआईबीइए) के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव देवीदास तुलजापुरकर ने व्यक्त किए। वे 21 जुलाई 2023 को संदर्भ केन्द्र द्वारा 'बैंकिंग का बदलता स्वरूप और आमजन पर उसका असर' विषय पर आयोजित व्याख्यान में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चार हजार से ज्यादा शाखाओं को बंद कर दिया है। अब ग्रामीण लोगों को बैंक की सुविधा हासिल करने के लिए दस, बीस, तीस या चालीस किलोमीटरों तक जाना होता है। सबको बैंकों से जोड़ने और बैंकिंग का डिजिटलाईजेशन करने के मकसद से पचास करोड़ जन–धन खाते खोल दिए गए हैं। मनरेगा की मजदूरी का पैसा भी लोगों के बैंकों में सीधा आता है लेकिन गाँवों में बैंक शाखाएँ बंद कर देने से लोगों की परेशानियाँ कम होने के बजाय बढ़ गयी हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से आम लोगों को जो कर्ज सात प्रतिशत या उससे भी कम पर मिल जाता था अब उन्हें माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फँसकर 40 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि बैंकों का विलय कर दिए जाने से सार्वजनिक क्षेत्र की 27 बैंकें घटकर अब मात्र 12 ही रह गई है। सरकार ने ग्रामीण अंचलों में कमीशन पर आधारित तीन लाख से ज्यादा बैंक मित्र नियुक्त किए हैं जो ग्रामीणों को 10 हजार रुपए तक का ऋण देते हैं। इन बैंक मित्रों को न अच्छी तनख्वाह मिलती है और न ही इन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह कोई सेवा–सुरक्षा या सुविधा ही हासिल है। इस व्यवस्था से दलाली, घूसखोरी बढ़ गई है। तुलजापुरकर ने कहा कि अब बैंकें ग्रामीण इलाकों में ऋण वितरण नहीं करती। ऋण ले चुके किसान भी इस उम्मीद में कर्जा नहीं लौटाते कि सरकारें उसे माफ कर देगी। इसके चलते जरूरतमंद किसान साहूकारों के जाल में फंस कर ऊंचे ब्याज पर ऋण लेने पर विवश हो जाते हैं और उसे चुका पाने में असफल रहने पर आत्महत्या कर लेते हैं। इस मामले में महाराष्ट्र का विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्र सुर्खियों में रहा है। वर्ष 1991 से आर्थिक नीतियों में आए बदलाव का असर कृषि एवं ऋण व्यवस्था पर भी पड़ा है। एक ओर किसानों को उसकी उपज का न्यूनतम मूल्य नहीं मिलता दूसरी ओर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत मिलने वाले राशन को घटा दिया है। किसानों के लिए बनी अनुदान योजनाओं में भी अनुदान कृषि उद्योगों, विद्युत वितरण कंपनियों, कृषि उपयोग में आने वाले वाहन निर्माताओं को दिया जाता है। इस अनुदान का लाभ भी किसानों को नहीं मिलता। बदली हुई आर्थिक नीतियों के चलते ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पहुंच 90 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत रह गई है। जिसका लाभ निजी बैंक और साहूकार उठा रहे हैं। देश बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति में पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि अकेले मुंबई और पुणे में ही जितना बैंक ऋण खेती के नाम पर बाँटा जाता है, जो मराठवाड़ा और विदर्भ के करीब 20 जिलों को मिलकर भी नहीं दिया जाता। विडंबना यह है कि विदर्भ और मराठवाड़ा में तो वाकई खेती होती है जबकि मुंबई और पुणे में खेती बराबर होती है। इसकी वजह यह है कि धीरे–धीरे खेती के लिए ऋण की परिभाषा को ही बदल दिया गया है और बैंक का ऋण किसानों को न दिया जाकर अब बड़ी–बड़ी कंपनियों और कारपोरेट को दिया जा रहा है।

बैंकें हर सेवा का शुल्क खातेदारों से वसूल रही है, चाहे ग्राहक उस सेवा का उपयोग भी न करता हो। देश में 200 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं। इन खातेदारों को लेनदेन की सूचना देने के लिए एसएमएस सेवा के नाम पर बैंकें 90 रुपए प्रति वर्ष वसूलती हैं। अधिकांश खातेदारों को इस सेवा की जरूरत भी नहीं होती। बैंकें मुनाफे में हैं लेकिन उसका लाभ बचतकर्ताओं को नहीं मिलता। बैंकें अब केवल मुनाफा कमाने के लिए ही काम कर रही है, सामाजिक सरोकारों से वे दूर हो गई है। जिन बैंकों का निजीकरण नहीं किया गया है तो उनकी सेवाएं निजी क्षेत्रों को सौंप दी गई है। ग्राहकों में सजगता और चेतना के अभाव के चलते सरकार मनमानी पर उतारू है।

गोष्ठी का संचालन करते हुए संदर्भ केन्द्र के विनीत तिवारी ने कहा कि करीब दस वर्ष पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में माइक्रोफाइनेंस के कारण अनेक लोग आत्महत्या के लिए विवश हुए हैं। बैंकें अब आम उपभोक्ता को ऋण न देकर माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण दे रही हैं जो आगे उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज पर ऋण देती हैं। उपभोक्ताओं को इसी शोषणकारी व्यवस्था से बचाने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उन्होंने कहा कि बैंक व्यवस्था और आर्थिक नीतियों को समझने की जरूरत है।

अर्थशास्त्री जया मेहता ने कहा कि अमूमन रिजर्व बैंक और सरकार एक दूसरे के खिलाफ रहती है। देश में दिया जा रहा मुद्रा ऋण राजनीतिक व्यवस्था है। यह कर्जा सरकार द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो इस वक्त भाजपा के कृपापात्र कारपोरेटों को दिया जा रहा है। इस ऋण का 10 लाख करोड़ रूपया डूब जाने का खतरा बना हुआ है।

बैंक अधिकारी संगठन के आलोक खरे के अनुसार एप आधारित ऋण कंपनियां गैर कानूनी हैं और उनसे बचा जाना चाहिए। इन कंपनियों के सर्वर देश के बाहर रहते हैं इसलिए उन पर शिकंजा कसना आसान नहीं होता। चर्चा में गिरीश मालवीय, चुन्नीलाल वाधवानी, एम. के. शुक्ला, अरविन्द पोरवाल, अर्चिष्मान राजू, ईशान बनर्जी, सुनील चंद्रन, प्रमोद बागड़ी, अरविन्द पोरवाल, विजय दलाल, हेमंत मालवीय, अभय नेमा, अशोक दुबे, रामदेव सायडीवाल, सुभद्रा, अथर्व शिंत्रे, हरनाम सिंह, रविशंकर तिवारी, आदि ने भी शिरकत की।

सभा में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार पर सरकार के रवैये की निंदा करते हुए दोषियों को दंडित करने की माँग की गई। हिंसा में लिप्त दोनों समुदायों से वार्ता के माध्यम से शांति स्थापित करने के प्रयास का आग्रह किया गया। प्रस्ताव का वाचन सारिका श्रीवास्तव ने किया।

मणिपुर की घटनाओं पर सौंपा ज्ञापन

सिवनी: राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत मणिपुर राज्य में आदिवासियों के साथ अश्लील हरकतें रेप और हत्याकांड तथा आगजनी हमले लूटपाट के विरुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं माकपा सिवनी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मणिपुर में बर्बरता पूर्वक हो रही और हत्या को रोक नहीं पाने के कारण मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मणिपुर की स्थिति को संसद और आम जनता से छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आदि की मांग की गई। मणिपुर में लगातार हो रही आगजनी लूटपाट रेप और एक महिला की बर्बर तरीके से हत्या को लेकर बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो, घटना को रोकने में नाकाम रहने तथा इस तथ्य को आम जनता से छुपाने के लिए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पद से इस्तीफा दो, संसद में मणिपुर पर बयान देने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, मणिपुर में शांति बहाल करो, मणिपुर राज्य में स्थिति को ना संभाल पाने के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करो, आदिवासियों पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे, साथ ही मध्यप्रदेश में तथा देश के अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कलेक्टर सिवनी के माध्यम से ज्ञापन देकर निवेदन किया गया है। इस आंदोलन के दौरान स्टूडेंट फेडरेशन के यीशु प्रकाश और नौजवान फेडरेशन के राहुल कुमार द्वारा क्रांतिकारी जनगीत प्रस्तुत किए गए।

अंत में धरना आंदोलन के पश्चात कलेक्टर सिवनी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमें किरण प्रकाश, डॉ. बी सी ओके, राजेंद्र चौहान, ओम प्रकाश, अशोक डेहरिया, डीडी वासनिक, तीरथ प्रसाद गजभिए, राजेंद्र प्रसाद जयसवाल, अंगद सिंह बघेल, डॉक्टर सतीश नाग, राजेंद्र चौहान, माया गढ़वाल, शकुन चौधरी, डीके तिरपुड़े, सुरेंद्र अहमद नायडू, मनीष सोनी, धनीराम बंदेवार आदि सम्मिलित रहे। आंदोलन में यह तय किया गया कि यदि मणिपुर और मिजोरम में शांति बहाल नहीं की गई तो राष्ट्रीय स्तर के साथ सिवनी में भी व्यापक आंदोलन किया जावेगा। जिससे अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब वर्ग पर इसी तरह का अत्याचार ना होने पाए।

हरियाणा में भयंकर बाढ़, 1978 जैसी विनाशकारी बाढ़

बीमारियों का खतरा, पशु चारे एवं पीने के पानी का संकट

दरियाव सिंह कश्यप

हरियाणा–हिमाचल आदि राज्यों में 8 जुलाई से हुई भयंकर बरसात के चलते हरियाणा की यमुना नदी, टांगरी, घग्घर, मारकंडा आदि नदियों में विनाशकारी बाढ़ आ गयी है। यमुना नदी में आई भारी बाढ़ ने यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली और बाद में फरीदाबाद व पलवल में रोद्र रुप दिखाया। सोनीपत, दिल्ली व फरीदाबाद में यमुना नदी और भी ज्यादा रोद्र रुप दिखाती यदि करनाल के टापू रामगढ़ व रिंडल गांवों के पास तथा पानीपत के पत्थरगढ़ व तामशाबाद में तटबंध न टूटता। तटबंध टूटने के चलते इन दोनों जिलों के 200 से ज्यादा गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया और दो दर्जन से अधिक गांवों का जिला मुख्यालयों से संम्पर्क टूट गया । यहीं नहीं इन जिलों में बाढ़ के चलते हजारों एकड़ धान, चारे, सब्जी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और बहुत सारे मकान गिर गए तथा बहुत सारे मकानों में दरार आ गई। जिनमें रहना खतरे से खाली नही है। हजारों लोगों को बाढ ग्रस्त इलाकों से निकाला गया।

यमुनानगर में यमुना का तटबंध तो नही टूटा लेकिन बारिश के प्रकोप के चलते बरसात का पानी भर गया और दर्जनों गावों में मकानों की छत गिर गई और अन्य में दरार आ गई। धान, हरे चारे व सब्जियों की फसल नष्ट हो गइ। टांगरी ने अम्बाला में कहर बरसाया, इस जिले के गावों तो बाढ़ की चपेट में आये वहीं अम्बाला शहर, अम्बालाकेंट पूरी तरह पानी में डूब गये, गलियों में नीचली मंजिल के मकानों में पानी भर गया और नागरिकों को खाद्यान्न, बिजली, पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ा। व्यापारिक संस्थानों, बाजारों आदि में भी पानी भर गया और बहुत सारा समान पूरी तरह नष्ट हो गया।

मारकंडा ने शाहबाद में रोद्र रुप अख्तियार किया और शाहबाद से आगे जाकर तटबंध टूटने के कारण मारकंड़ा का पानी सैंकड़ों गांवों की फसल व काफी मकान क्षतिग्रस्त कर गया। जनसुई हैड, ठोल के पास नरवाना ब्रांच व एसवाईएल नहरें टूट गई तथा झांसा के बाद नरवाना ब्रांच टूटने के कारण कुरुक्षेत्र जिलें में हजारों एकड़ धान, चारे व सब्जियों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। इस्माईलाबाद के आगे मारकंडा ने तबाही मचाई जिसके चलते टबरा सहित दर्जनों गांवों का इस्माईलाबाद से ही सम्पर्क कट गया और ग्रामीणों के सामने खाद्यान्न सहित पीने के पानी का भारी संकट आया।

मारकंडा–घग्घर नदी ने कैथल जिले को अपनी चपेट में लिया और गुहला–चीका में फसलों, मकानों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। फतेहाबाद के टोहाना व रतिया शहरों में पानी भर गया। रतिया–भूना सड़क को दीवाना गांव के पास ग्रामीणों ने तोड़ दिया और गांव को डूबने से बचाया गया। इस जिले में घग्घर–मारकंडा (जो दोनों नदियां एक ही हो गई) के साथ–साथ रंगोई नाले ने भी पास लगते गांवों की फसलों को तबाह किया।

जब यमुना नदी में पानी कम हो रहा था उसी समय पश्चिम हरियाणा के सिरसा जिले में घग्घर नदी ने बरसात के साथ मिल कर तबाही मचाई। नेजाड़ला कलां के पास घग्घर में अंदरुनी बांध टूट गया और दर्जन भर के किसानों की फसलों को नष्ट किया। ओटू झील के ओवरफ्लो होने के कारण नदी के बाहरी तटबंघ टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया और ग्रामीणों के प्रयास से हजारों एकड़ में खड़ी धान व अन्य फसलों को बचाया जा सका।

सोनीपत जिले में गढ़ी बलिन्दा (बेका) से लेकर मनोली टोकी तक 40 किलोमीटर लम्बे यमुना नदी के तटबंध के साथ लगते दो दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का असर देखने को मिला। यहां की हजारों एकड़ मिर्च, करेला जैसी सब्जियों एवं धान की फसल नष्ट हो गई। यहां पर अधिकतर किसान भूमिहीन किसान हैं जो भारी रकम पर जमीन ठेके पर लेकर कास्त करते हैं। इन किसानों पर दोहरी मार हो गई जो एड़वांस में ठेके की रकम जमीन मालिक को देते है और पूरे परिवार के साथ–साथ मजदूरों की मदद भी खेती करने में लेते हैं। इस तरह फसल नष्ट होने से ऐसे किसान बुरी तरह टूट जाते हैं।

फरीदाबाद व पलवल जिलों में यमुना नदी की बाढ़ ने काफी रकबा प्रभावित किया है। बाढ़ के चलते हरियाणा में लगभग 50 लोग अकाल मौत का शिकार हुए हैं, 1500 के करीब गांवों में बाढ़ से सैंकड़ों घर नष्ट हुए हैं और हजारों मकानों का छोटा–मोटा नुकसान हुआ है। सैंकडों जगहों पर सड़कें टूटी है और दर्जनों पुल टूट गये हैं, क्षतिग्रस्त हुए है। इस बार 45 वर्ष पहले 1978 में आई बाढ़ से भी ज्यादा विकराल बाढ़ आई है। उस वर्ष यमुना के साथ लगते जिले प्रभावित हुए थे जबकि इस बार की बाढ़ में हरियाणा के 12 जिले प्रभावित हुए है।

भाकपा के राज्य सचिव ने सोनीपत, करनाल व कुरुक्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ तीनो जिलों के 4 दर्जन से अधिक बाढ़ प्रभावित गांवों में ग्रामीणों से सम्पर्क किया और भाकपा की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। यमुनानगर में पार्टी की ओर से बाढ़ राहत के लिये मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त व बिलासपुर एसडीएम को मांगपत्र दिया गया। कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा आदि जिलों के भाकपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से सम्पर्क किया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हरियाणा राज्य कौंसिल समझती है कि अतिवृष्टि के चलते बाढ़ आना प्राकृतिक है लेकिन बरसाती नदी–नालों की सफाई, तटबंधों की मजबूती, जमीन कटाव से रोकने के लिये ठोकर आदि लगाने के काम समय रहते प्रशासन को करने चाहिए। राज्य व केन्द्र सरकार बाढ़ बचाव के लिये बहुत सारा पैसा देती है लेकिन प्रशासन उस पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा बरसात व बाढ़ आने के समय ही खर्च करता है। राज्य सरकार को इस पैसे की जांच–पड़ताल करनी चाहिए और इसमें दोषी लोगों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

दूसरी ओर यमुना नदी का जलस्तर घटने के साथ ईख, ज्वार आदि फसलों सहित हरियाणा की सैंकड़ों एकड़ जमीन यमुना में समा रही है और जमीन का कटाव अभी भी जारी है। प्रशासन को अप्रैल महीने से पत्थरों की ठोकरें लगा कर इस हानि से राज्य के गरीब किसानों को बचा सकता था लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नही है। सरकार–प्रशासन की लापरवाही से राज्य के सैंकड़ों परिवार फसल के साथ–साथ अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठें।

नदियों में जलस्तर कम हो रहा है लेकिन बहुत सारे गांवों में अभी पानी भरा हुआ है। ज्यों–ज्यों पानी कम हो रहा है बाढ़ग्रस्त गांवों व बस्तियों में दस्त, बुखार, चर्मरोग, डेंगु आदि बीमारियां फैल रही हैं। भूसा व हरे चारे की फसल नष्ट होने के कारण पशुओं के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है। धान की फसल नष्ट होने के चलते धान की पौध (पनीरी) तैयार न होने के कारण अब धान लगाने के लिए किसानों को एक महीना इंतजार करना होगा।

राज्य सरकार ने हरियाणा के 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है और मृतकों के परिवारों, पशुपालको व क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता देने की घोंषणा की है जो नाकाफी है। बाढ़ग्रस्त एरिया में सरकार को पानी निकासी, सड़कों की मरम्मत, बीमारियों से बचाव के लिए युद्धस्तर पर काम करना होगा। प्रभावित किसानों–मजदूरों को कर्ज से पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में कदम उठाने होगें। अकाल मौत के शिकार हुए नागरिकों के परिवार को प्रति मृतक कम से कम 30 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने, प्रति एकड़ 40 हजार रुपये सहायता देने, ठेके व बटाईदार किसानों को भी आर्थिक सहयोग करने, बाढ़ का पानी निकालने को प्राथमिकता देने, गिरे हुए मकान मालिकों को प्रति मकान 5 लाख रुपये देकर पुनः निर्माण कराये जाने चाहिए। पशुओं के लिये चारे का प्रबंध, बिजली बिलों से राहत व खराब ट्यूबवैलों की मरम्मत कराने में सहायता देने आदि कामो को प्राथमिकता के तौर पर करवाना चाहिए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हरियाणा राज्य कौंसिल बाढ़ प्रभावित जिलों के सचिवों से अनुरोध करती है कि वे अपने साथियों के साथ अपने जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को समझे और प्रशासन तक उनकी मांगों को पहुंचाए।

नरेन्द्र सिंह नेगी उत्तराखण्ड़ कंट्रोल कमीशन के चैयरमेन बने

देहरादूनः भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी उत्तराखण्ड राज्य कंट्रोल कमीशन के नए चेयरमैन वरिष्ठ साथी नरेंद्र सिंह नेगी जी को सर्वसम्मति से चुना गया। इस से पहले साथी एमएस त्यागी ने स्वास्थ्य के कारण उक्त पद से इस्तीफा दे दिया था। एन एस नेगी पूर्व में पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में, पार्टी के मुखपत्र के व्यवस्थापक तथा पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के तीन बार आमंत्रित सदस्य रह चुके हैं। पिछले 10 वर्षो से उन्होंने अपनी पार्टी सदस्यता उत्तराखण्ड पार्टी में ट्रांसफर करवा दी थी।

साथी एन एस नेगी पिछले 52 सालों से पार्टी के सदस्य हैं 2014 में पार्टी ने उन्हें पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से पार्टी का प्रत्याशी भी बनाया था। पार्टी की तरफ से वे कई समाजवादी देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। सोवियत संघ, चाइना, बुलगारिया, जर्मनी,वियतनाम, अफगानिस्तान, नेपाल तथा सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि। साथी नगी जी ने राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। 1973 में जमा खोरी के किलाफ आंदोलन में वे 4 दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रहे थे।

भाकपा ने 25 जुलाई को देशभर में मनाया मणिपुर ....

पेज 1 से जारी...

फल स्वरुप दोनों समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हो गया और उसका नतीजा मैती और कूकी समुदायों के बीच हिंसा के रूप में निकला। आरएसएस ने भी वहां के नागरिकों को धार्मिक आधारों पर बांटने के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी। दुष्प्रचार भी हिंसा का कारण बना।

मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने समाज के जटिल मुद्दों को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जमीन के जटिल मुद्दे, विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृक मुद्दों की पहचान, वनों की जमीन के दुरुपयोग, बेरोजगारी, सभी जातीय समूह को शिक्षा की बराबर पहुंच, अफीम की खेती, घाटी और पहाड़ी इलाके के विभिन्न भूमिगत सशस्त्र गुटों को नियंत्रण में रखने, म्यांमार से बेरोकटोक घुसपैठ एवं अनेक अन्य मुद्दों का समाधान न निकलने के कारण वर्तमान जातीय टकराव हुआ है।

वास्तव में तो भारतीय जनता पार्टी की नितांत असफलता और मुख्यमंत्री की हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने की कुटिल योजना ने समस्या को अत्यंत गहरा दिया है।

2 महीने व्यतीत होने के पश्चात भी आज भी हिंसा जारी है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि क्योंकि सभी पक्षों के बीच में अविश्वास और नफरत मौजूद है और हिंसा जारी है तो मणिपुर में अमन चैन को बहाल करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। संवाद एवं सुलह समझौते के जरिए सभी मतो और लोगों को विश्वास में लेकर संकट का एक राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। उसी प्रक्रिया में इस जारी संकट का कोई समाधान निकल सकता है।

ज्ञापन में उल्लेख है कि इस संदर्भ में एक तथ्य अन्वेषी दल भेजने की भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की पहल और बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा) के संसद सदस्यों द्वारा मणिपुर के दौरे की पहल को स्थिति को समझने और मणिपुर मैं सभी समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण करने की दिशा में गंभीर कोशिश के तौर पर सराहना की गई।

यद्यपि यह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन के नेताओं के विरुद्ध राज्य सरकार ने विभिन्न धाराओं में मुकदमें कायम करवा दिए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मान्यता है कि संवाद एवं सुलह समझौते के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए तत्काल निम्न कदम उठाए जाने चाहिए।

1. मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो।

2. जिन आतंकवादी ग्रुप और व्यक्तियों के पास गैरकानूनी हथियार हैं उन तमाम को शस्त्र विहीन किया जाए और तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए।

3. म्यांमार से घुसपैठ बंद की जाए। सीमा सुरक्षा दल को इस संदर्भ में समुचित कदम उठाने चाहिए।

4. आरक्षित वन भूमि पर अफीम की खेती बंद की जाए और अडानी समूह को खनन एवं अन्य व वाणिज्यिक कार्यकलाप जिससे जमीन का चरित्र बदल जाएगा; को 56000 एकड़ जमीन देने के फैसले का विरोध किया जाए।

5. लोगों को जिस पैमाने पर तकलीफ पहुंची हैं और उनकी जितनी अधिक शिकायतें हैं और उन्हें जितना भारी नुकसान पहुंचा है उसे देखते हुए सभी पक्षों के लोगों को मुआवजे का स्पेशल पैकिंज दिया जाए। उनके लिए राज्य द्वारा पुनर्वास के कदम उठाए जाएं और एक समयबद्ध तरीके से उनके लिए रोटी रोजी की व्यवस्था की जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार को बिना पक्षपात और बिना भेदभाव यह काम सुनिश्चित करना चाहिए।

6. आवश्यक सामानों एवं दवाओं के आवागमन के लिए मणिपुर के तमाम राजमार्गों को खोल दिया जाए।

7. भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की महासचिव एनी राजा, सचिव निशा सिद्धू एवं अन्य के खिलाफ दायर मामले जो हास्यास्पद एवं मनगढ़ंत है वापस लिए जाएं।

अरविंद राज स्वरूप ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की भू क्षेत्रीय अखंडता और जनता की एकता के प्रति अपनी सोच को एक बार फिर दौर दोहराती है। जिसका उल्लेख ज्ञापन में भी किया गया है।

उन्होंने कहा, ज्ञापन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मणिपुर की स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री की लगातार खामोशी की निंदा की गई है। यह खामोशी पुष्टि करती है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। जिसकी विश्व भर में आलोचना हो रही है और देश की छवि खराब हो रही है। वायरल वीडियो के संबंध में उनका दिया गया बयान जिसमें उन्होंने इस कांड की निंदा की है नाकाफी है, क्योंकि उन्होंने उस बयान को दूसरे प्रांतों की घटनाओं

से जोड़ दिया जबकि अन्य प्रांतों में इस प्रकार की एक भी घटना नहीं हुई। इस प्रकार की घटना सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में ही देखी गई है।

राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप ने कहा कि आज प्रदेश के सोनभद्र, चित्रकूट, इलाहाबाद, गोंडा प्रतापगढ़, भदोही, बाराबंकी कानपुर नगर, जालौन, सुल्तानपुर,लखनऊ, गाजीपुर, अलीगढ़, पीलीभीत, बलरामपुर, फतेहपुर, एवं अन्य अनेकों जिलों से खबरें आ चुकी हैं। सूचना के अनुसार प्रदेश के लगभग 40 जिलों में कार्यक्रम संपन्न हुआ है।

बाराबंकी (उप्र)

देश के पूर्वोत्तर में मणिपुर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है, प्रदेश में कानून व्यवस्था लगभग 3 माह से समाप्त हो गई है। 3 मई 2023 से लेकर अब तक 142 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, 1000 से अधिक लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, 70 हजार से अधिक लोग अपना घर द्वार छोड़कर शरणार्थी शिविरों में शरण लिए हैं या निकट के राज्यों में पलायन कर चुके हैं। 19 जुलाई 2023 को दो लड़कियों को बंधक बनाकर नंगा करके जुलूस निकालकर सामूहिक बलात्कार किया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उक्त दोनों महिलाओं में से एक ने बताया कि मणिपुर पुलिस ने ही उनको भीड़ के हवाले किया था, मणिपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री ने इंडिया टुडे को बातचीत में बताया कि इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज भी है। यह बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन ने कही।

प्रदेश में हिंसा जारी हैं, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ साबित हो गया रहे हैं, गोलियां चल रही हैं जनता के मकान जलाए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में आपका हस्तक्षेप आवश्यक है। यह बात पार्टी सचिव बृजमोहन वर्मा ने कही।

राष्ट्रपति से मांग करते हुए पार्टी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को बर्खास्त करो। राष्ट्रपति को सम्बोधित करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है।

ज्ञापन पर महेंद्र यादव, जिला आशीष शुक्ला विनय कुमार सिंह (जिला अध्यक्ष उप्र किसान सभा) संदीप तिवारी, शिवदर्शन वर्मा, कोषाध्यक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, प्रवीण कुमार सह सचिव भाकपा, महेंद्र यादव जिला अध्यक्ष एआईएसएफ, आशीष शुक्ला प्रदेश उपाध्यक्ष एआईवाईएफ, मुनेश्वर प्रसाद राज्य परिषद सदस्य किसान सभा, गिरीशचंद्र उपाध्यक्ष किसान सभा, रामनरेश महामंत्री किसान सभा, अमर सिंह को उपाध्यक्ष किसान सभा, किसान श्याम सिंह, नैमिष, राजेंद्र बहादुर सिंह एडवोकेट, नीरज वर्मा, दीपक शर्मा, आशीष शुक्ला, जितेंद्र श्रीवास्तव, जित्तू सच्चिदानंद, शैलेंद्र मिश्रा, संदीप तिवारी, अभय शर्मा, सर्वेश यादव, कुलदीप यादव, रामनरेश, अमर सिंह गुड्डू, विनय सिंह, राजकुमार आदि प्रमुख नेताओं ने भी हस्ताक्षर किये हैं।

गोवाहटी (असम)

असम में 12 पार्टी विपक्षी मंच ने मणिपुर में शांति और सद्भाव की बहाली के लिए गुवाहाटी में एकजुटता बैठक का आयोजन किया और केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की निंदा की। विपक्षी मंच के नेताओं ने मणिपुर में हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर सुप्रीमो नरेंद्र मोदी और बीरेन सिंह की तीखी आलोचना की। उन्होंने बताया कि यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को मणिपुर की ज्वलंत स्थिति पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए 79 दिन चाहिए। तो यह हमारे महान देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। वहां मौजूद सभी विपक्षी नेताओं ने सुप्रीमो नरेंद्र मोदी और बीरेन सिंह दोनों की तीखी आलोचना की। उन्होंने जाति, समुदाय और धर्म से परे महिलाओं के खिलाफ अमानवीय अत्याचार की भी आलोचना की। और उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार करने वाले दोषियों को सजा देने की मांग की।

दूसरी ओर, भाकपा असम महिला संघ, एआईएसएफ, एआईवाईएफ और एआईकेएस के जन मोर्चे ने भी 21 जुलाई 2023 की शाम को मणिपुर में हिंसा रोकने और शांति और सद्भाव की बहाली के लिए हमारे पार्टी मुख्यालय के सामने एक मोमबत्ती कार्यक्रम का आयोजन किया है। राज्य महासचिव असोमी गोगोई एएमएस, एआईवाईएफ के राज्य अध्यक्ष कृष्णा गोगोई और एआईकेएस के राज्य सचिव जयंत गोगोई ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया और दोनों डबल इंजन सरकार की आलोचना की।

सुकमा (छत्तीसगढ़)

मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ भारतीय महिला फेडरेशन जिला सुकमा के द्वारा 23 जुलाई 2023 को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिहं का पुतला दहन कर विरोध किया गया। विगत तीन माह से अधिक दिन से मणिपुर मे लगातार हिंसा हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। विगत कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। इसमें जघन्य हरकत महिलाओं के साथ की गयी, महिलाओं को बलात्कार कर खुलेआम सार्वजनिक जगह में नग्न किया गया। ऐसे हालात मे मणिपुर जल रहा है। वहां का मुख्यमंत्री एन बीरेन और भाजपा सरकार क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पर क्यों

शेष पेज 15 पर...

मणिपुर: बढ़ता भारत या सुलगता भारत

महेश राठी

गिद्धों के लिए खून की खुशबू और फैले मांस के लौथडे होते हैं जश्न की आमद। वे इस जश्न का इंतजाम करते हैं। अथवा करते हैं इसका इंतजार, एकदम खामौश और ध्यानमग्न। परंतु ऐसा भी नहीं कि वे नहीं बोलते, वो बोलते हैं। वे अक्सर तब बोलते हैं जब उनकी सत्ता को खतरा होता है। वे तब लब खोलते हैं जब उन्हें कुर्सी बचानी होती है। वे तभी बोलते हैं जब उनका जातीय जनाधार खतरे में होता है। वे अक्सर खामोश रहते हैं जब मोच लिंचिंग में लोग मारे जाते हैं। वे चुप रहते हैं जब लव जेहाद के नाम पर कत्ल हो जाते हैं। वे चुप रहते हैं, जब दंगें में गर्भ से निकालकर अजन्में बच्चों को तलवारों पर टांगा जाता है। वे हमेशा चुप रहते हैं जब दंगा पीड़ित बेघर, बे–दर होकर खुले आसमान के नीचे होते हैं।

परंतु वे अब बोले हैं, फिर बोले हैं। जब मणिपुर में दो औरत की इज्जत को तार तार कर दिया गया। उन्हें वहशी दंगाईयों ने अपने बहुसंख्यिकी अभिमान में सरे राह नंगा घुमाया। वे बोले कि बोलना उनकी मजबूरी थी। वे बोले कि उनका गोदी मीड़िया चाहकर भी इस घटना को खबर बनने से रोक नहीं सका था। वे बोले कि उनका मीड़िया कमजोर निकला। वे बोले कि उनकी खामोशी दुनिया में उनकी महान छवि को तार तार कर रही थी। इस बोलने वाली जबान को आप क्या नाम दें। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। आप आजाद हैं।

मणिपुर जल रहा है। छोटी कंक्रीट की बस्ती हो या घने जंगल के बीच छोटा सा गांव सभी जगह धुंआ है, आग की लपटे हैं। वाहन हो, अथवा घर या मॉल या फिर इंसानी जिस्म, उनकी आत्मा, उनके दिल, उनकी रूहें सभी कुछ जल रहा है, सुलग रहा है।

सियासत की बिसात पर मोहरा बने इंसानों ने सब कुछ जला दिया। आपसी भाईचारा, सौहार्द, विश्वास, असल इंसानी फितरत और इंसानियत। सभी कुछ।

इंसानियत के इस कत्ल का साक्ष्य मुख्यमंत्री का यह बयान है कि ऐसी यहां सैंकड़ों घटनाएं हो रही हैं। वे आगे बोलते हैं कि इस तरह की सौ के करीब एफआईआर हैं। इन आरोपों को मत सुनो जमीनी हकीकत को सुनो।

जमीनी हकीकत है बहुसंख्यक वोट का गणित। बहुसंख्यक वोट का गणित और पहाडों के गर्भ में छुपे कीमती खनिजों की चाह, जो इन्हें गूंगा बनाती है। इन्हें रक्तपात को छुपाने ढकने का गुर सिखाती है। औरतों को नंगा करके घुमाने पर आंख मुंदना सिखाती है। इन्हें सत्ता के लालची बुत बनाती है।

इनकी खामोशी कितनी रणनीतिक है। इसे इनके प्रवक्ताओं के तर्क और समर्थकों के ट्रोल बताते हैं। उनके तर्क बलात्कारियों को दो खेमों में बांटते हैं। उनके बलात्कारी और उनके विरोधियों के बलात्कारी। ऐसे तर्क गिद्ध गिरोह औपचारिक भाषा और संस्कृति

शेष पेज 14 पर

मणिपुरः बढ़ता भारत या सुलगता...

पेज 13 से जारी...

का पता देते हैं। वो संस्कृति जो हत्या का समाधान हत्या और बलात्कार का समाधान बलात्कार सिखाती है। क्योंकि लाशों और बलात्कार पीडितों को सिर्फ इंसान समझना उनकी सियासत को कमजोर बनाता है। इसीलिए वो हर चीज बांटते हैं, जिंदा इंसानों से लेकर लाशों तक, सभी कुछ!

भारत के उत्तर–पूर्वी राज्य मणिपुर के कस्बों और गांवों में, जातीय हिंसा भड़कने के बाद 155 से अधिक लोग मारे गये हजारों जख्मी हुए और 70 हजार से ज्यादा विस्थापित होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं।

अब इस हिंसा का असर पडोसी राज्यों पर भी दिखने लगा है। मिजोरम में मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोग डरकर अपने राज्य मणिपुर लौटना चाह रहे हैं। मिजोरम की प्रतिक्रिया से लगता है कि गिद्धों के जश्न का मौसम आ गया है। अब मिजोरम नेशनल फ्रंट जिसने मौजूदा सरकार के साथ समझौता किया, मिजोरम में बसे मणिपुर वासियों को धमका रहा है।

3 मई से शुरू हुई हिंसा और तनाव के थमने और शान्ति कायम होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। उत्तर पूर्व एक गृहयुद्ध के हालात की तरफ बढ़ता दिख रहा है। उत्तर पूर्व के निवासियों में बांटने वाली नफरत और शक की खाई बढ़ती दिख रही है।

आइये, इस दर्द, दहशत और शर्मिंदगी को कुछ भयावह तस्वीरों में पढ़ें:

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

भाकपा ने 25 जुलाई को देशभर में मनाया मणिपुर ....

पेज 12 से जारी...

चुप हैं। महिलाओ को बलात्कार व जघन्य हरकत करने वाले दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने, मणिपुर में शान्ति बहाल करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जल्द कार्यवाही नही करने पर आक्रोशित होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मणिपुर मुंख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध किया गया।

इस अवसर पर महिला फेडरेशन के पदाधिकारी कुसुम नाग, अराधना मरकाम, मंजू कवासी, कलमू आयती, रामा सोडी, राजेश नाग, महेश कुंजाम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड़

मणिपुर की घटना पर उत्तराखंड में चमोली, देहरादून, हरिद्वार में प्रदर्शन किया गया भारत सरकार से मणिपुर में शीघ्र शांति बहाल करने की मांग की गई। दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और महिला फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल पर एफआईआर दर्ज की गई उसे अविलंब वापिस किया जाये।

सिरसा, हरियाणा

पिछले लगभग 3 महीने से मणिपुर में फैले जातीय दंगे व अशांति को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान किया कि भाजपा की केंद्र व मणिपुर सरकार दोनों के खिलाफ 25 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएं। सिरसा हरियाणा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सर्व कर्मचारी संघ द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया व प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर राष्ट्रपति के नाम मणिपुर में शांति बहाली को लेकर एक मांग पत्र दिया गया इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड स्वर्ण सिंह विर्क, राज्य सह सचिव तिलक राज विनायक, जिला सचिव जगरूप सिंह, डॉ. सुखदेव सिंह जम्मू राज्य संयोजक अखिल भारतीय किसान सभा 1936 (अजय भवन) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा, बलबीर कौर गाँधी एडवोकेट जनवादी महिला समिति, मदनलाल खोट सर्व कर्मचारी संघ ने मणिपुर पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर में लगभग 3 महीने से जातीय दंगे फैले हुए हैं 70000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, 150 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है लेकिन मणिपुर की सरकार ने अपराधियों पर कोई कार्यवाही ना की है, व केंद्र सरकार भी मणिपुर पर लगभग चुप है। कम्युनिस्ट नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र के माध्यम से यह मांग की के मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जातीय दंगों में जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करें। मणिपुर में अफीम की खेती पर रोक लगाई जाए, जिन लोगों के पास गैरकानूनी हथियार हैं, उनको जब्त किया जाए, अदानी समूह की मणिपुर के क्षेत्र में खनन को लेकर पाबंदी लगाई जाए, अदानी ग्रुप को दी गई 56000 एकड जमीन के फैसले को रद्द किया जाए, महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव एनी राजा व सचिव निशा सिद्धू पर बनाए गए झूठे केस रद्द किए जाएं, नेताओं ने बताया कि भाजपा की मणिपुर व केंद्र की सरकार दोनों ही महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, व भारतीय एकता के लिए खतरा है। भाजपा सरकार की देश में संविधान विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि मणिपुर व देश के अन्य सभी भागों में शांति की बहाली हो सके सके। कर्मठ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओ ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर व भाजपा की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया वह मणिपुर की जनता के साथ एकजुटता जाहिर की। इस अवसर पर प्रितपाल सिद्धू जिला सह सचिव सीपीआई बलराज सिंह बनी, हैप्पी बक्शी, राजकुमार शेखुपुरिया, इकबाल सिंह ने जडेला कला शिंदे पाल चौबुर्जा, रेशम सिंह, हमजिन्दर सिंह, हरजिंदर भंगू आदि सैंकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दिल्ली

25 जुलाई को रात 8 बजे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (पश्चिमी दिल्ली जिला परिषद्) की ओर से मंगोलपुरी, नई दिल्ली के एल एवं एम ब्लाक में कैंडल मार्च निकाला गया तथा एल–के ब्लाक की मार्केट के चौक पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य तथा दिल्ली के सचिव मंडल सदस्य व जिला सचिव शंकर लाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद् सदस्य व एटक, दिल्ली राज्य कमेटी के उपमहासचिव मुकेश कश्यप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दिल्ली राज्य परिषद् के सदस्य तथा एटक, दिल्ली राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष राजेश कश्यप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिमी दिल्ली के सचिवमंडल के सदस्य तथा एटक, दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य राममूर्ति ने जनसभा को सम्बोधित किया। सभी वक्ताओं ने माँग की कि मणिपुर में जारी हिंसा पर मोदी सरकार तत्काल रोक लगाये तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की महिला नेत्रियों पर दर्ज एफआईआर तत्काल निरस्त की जाये।

कैंडल मार्च में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य अंजलि, मोनिका, आशा, पुष्पा, सरिता, गीता, माया, सविता तथा डाव आर एन भारद्वाज, मुव अली , नितिन, कालू कुमार, विवेक, आदि कार्यकर्ता सम्मिलित थे।

उत्तरी दिल्ली

25 जुलाई सीपीआई राष्ट्रीय परिषद आवाहन पर मणिपुर में पिछले 80 दिनों से ज्यादा दिनों से हिंसा के विरुद्ध सीपीआई उत्तरी दिल्ली जिले ने ऐतिहासिक सब्जी मंडी घंटा घर के क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व शंकरलाल सीपीआई राष्ट्रीय परिषद सदस्य, संजीव कुमार राणा, सचिव सीपीआई उत्तरी दिल्ली जिला, धरमपाल, इस्लाम, देवेंद्र, साजदा बेगम, इस्लाम, अमीर अहमद, बबन कुमार सिंह दिल्ली राज्य सीपीआई परिषद सदस्य आदि ने किया।

बिहार

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बिहार राज्य के जिले–जिले में पार्टी में प्रतिरोध खड़ा किया गया और मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई।

अब तक राज्य मुख्यालय में प्राप्त सूचनानुसार मधुबनी मुख्यालय सहित कई अंचलों, बेगुसराय जिला मुख्यालय एवं अन्य अंचलों,पं. चंपारण, पू. चंपारण, दरभंगा, पटना, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, शेखपुरा सहित विभन्न जिले में प्रदर्शन, धरना, सभा आदि रूपों में प्रतिरोध किया गया।

पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने अल्प सूचना पर जिला इकाइयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए पार्टी साथियों, हमदर्दो को धन्यवाद किया है।

लुधियाना (पंजाब)

भाकपा के मणिपुर एकता दिवस मनाने के राष्ट्रव्यापी आहवान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भारत) जिला लुधियाना द्वारा पंजाब स्त्री सभा जिला लुधियाना, इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था और ऐसे अन्य सामाजिक संगठनों के साथ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य में हिंसा को नियंत्रित करने में केंद्र और मणिपुर राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि स्थिति दिन–ब–दिन बिगड़ती जा रही है, प्रधानमंत्री ने इन परिस्थितियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब मणिपुर जैसा अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य जल रहा था, तब प्रधानमंत्री विदेशी दौरों में व्यस्त थे। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि सरकार को 4 मई को महिलाओं की नग्न परेड और बलात्कार की भयावह हिंसा की पूरी जानकारी थी। लेकिन उन्होंने इसे छुपाया। यह महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग को 9 मई को घटना के बारे में एक ईमेल मिला। यह माना नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री की लगातार चुप्पी हिंसा के प्रति उनके अंतर्निहित समर्थन को दर्शाती है।

यह बेहद निंदनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हमेशा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है। यह 2002 के गुजरात की याद दिलाता है जब उन्होंने उस हिंसा पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी जिसके कारण नरसंहार हुआ था और लगभग 2500 लोग मारे गए थे। तब भी गुजरात और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। 20 जुलाई को मणिपुर के बारे उनके भाषण के शब्द राज्य में हिंसा और पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से ज्यादा राजनीतिक थे। यह उनकी मानसिकता का परिचायक है। इतिहास हमें बताता है कि जब हाथरस की गरीब लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर बाद में उसके परिवार के सदस्यों के बिना पुलिस ने उसे जला दिया, तो उनहोंने एक शब्द भी नहीं कहा, बिलकिस बानो परिवार के बलात्कारियों और हत्यारों की रिहाई पर एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों के साथ जिस तरह क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया और यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, वह हमारे सामने है। वक्ताओं ने कहा कि मणिपुर में गुंडागर्दी और हिंसा के बाद डबल इंजन सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मणिपुर पर केंद्र सरकार की चुप्पी हिंसा को मौन समर्थन का प्रतीक है। राज्य व केंद्र सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पूरी तरह से असंवेदनशील सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है।

पंजाबी भवन से लघु सचिवालय तक इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। देश के राष्ट्रपति को ई–मेल के जरिए केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। बोलने वालों में डीपी मौर, भाकपा जिला सचिव, डॉ. अरुण मित्रा, एम एस भाटिया, चमकौर सिंह, विजय कुमार, केवल सिंह बनवैत, गुरमेल मेल्डे, विनोद कुमार, अवतार छिब्बर, डॉ. गुरचरण कौर कोचर–अध्यक्ष पंजाब महिला सभा लुधियाना, कुसुम लता, महासचिव भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था, सुषमा उबराय, अनु भट्टी, कुलवंत कौर, शकुंतला देवी, अमृतपाल सिंह, हरबंस सिंह गिल, सिकंदर सिद्धू, बापू बलकौर सिंह गिल, डॉ. बीएस औलख, मलकीत सिंह मालरा आदि शामिल थे।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 30 जुलाई – 5 अगस्त, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 28.7.2023

देश को भाजपा से मुक्त कराना होगा: भाकपा

कन्नूर: भाकपा महासचिव डी राजा देश को भाजपा राज से मुक्त कराने के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं। वह एनई बलराम–पीपी मुकुंदन मेमोरियल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले कुछ समय से संसद में गतिरोध बना हुआ है। यह ऐसे समय में हुआ है जब संसद में कई मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है। वजह है मणिपुर में चल रहे दंगे. जब मणिपुर जल रहा था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने केवल तभी जबान खोली जब दो महिलाओं को नग्न और अपमानित करने की घटना सामने आई। मोदी की हमेशा डबल इंजन सरकार का दावा करने वाली सरकार मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, इसका कारण यह है कि वे ऐसा नहीं चाहते हैं।

भाजपा बांटो और राज करो का एजेंडा लागू कर रही है। यही कारण है कि जब दो समूह आपस में भिड़ते हैं तो मणिपुर आंखें मूंद लेता है। लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात करते समय, जो लोग इसकी बात नहीं मानते, वे समान आचार संहिता कानून बनाने की राह पर चल रहे हैं।

वे मनु स्मृति में विश्वास करते हैं। कम्युनिस्टों को जेल भेजा जा सकता है, नुकसान पहुँचाया जा सकता है और मार दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें कभी हराया नहीं जा सकता। 2024 देश में होने वाले चुनाव अहम हैं। भारत को भाजपा शासन से मुक्त कराना ही लक्ष्य होना चाहिए। राजा ने कहा कि जब हम कम्युनिस्ट नेताओं एनई बलराम और पीपी मुकुंदन और उनके बहादुर संघर्षों को याद करते हैं, तो हमें देश की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचना चाहिए।

सीएन चंद्रन, भाकपा राज्य परिषद सदस्य और एनई बलराम ट्रस्ट के अध्यक्ष ने समारोह की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और एनएफआईडब्ल्यू महासचिव एनी राजा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पी संतोष कुमार एमपी, पूर्व राज्य सचिव पन्नियन रवींद्रन, नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष सीपी मुरली और अन्य ने बात की। जिला सचिव सीपी संतोष कुमार ने स्वागत किया।

भाकपा ने बारसोई पुलिस गोलीकांड की निंदा की

पटना, 27 जुलाई, 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कटिहार जिले के बारसोई में बिजली विभाग कार्यालय के सामने 29 पंचायतो के जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता के द्वारा शांतिपूर्ण आयोजित प्रदर्शन पर हुई पुलिस फायरिंग की निंदा की है, तथा पुलिस फायरिंग में मृत दो व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने और मामले की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि बारसोई बिजली कार्यालय के सामने प्रखंड के 29 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता द्वारा बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित की गयी थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से दो युवा सोनू कुमार और खुशी की मौत हो गई और एक व्यक्ति की हालत चिंताजनक है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पुलिस की कार्रवाई निंदनीय है! उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण बिहार भीषण सूखे एवं गर्मी की चपेट में है। ऐसी स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण पूरे राज्य में बिजली की मांग को लेकर लोग आंदोलित है। बिजली वितरण कंपनी इस मांग को पूरा करने में अक्षम साबित हो रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है। जो बिजली मिल भी रही है वह महंगी मिल रही है। केंद्र से पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलने के कारण राज्य में बिजली की समस्या उतपन्न हो गयी है। भाकपा राज्य सचिव ने राज्य सरकार से अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने और जरूरत के हिसाब से बिजली की आपूर्ति करने की मांग की है। साथ ही बारसोई गोलीकांड की जांच करा दोषी पर कार्रवाई करने तथा मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.